

वायु प्रदूषण का बढ़ने लगा खतरा, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा रिस्क, ऐसे करें बचाव

इस महीने की शुरुआत से ही दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है. ऐसे में डॉक्टरों ने अलर्ट किया है. डॉक्टरों का कहना है कि अभी से लोगों को वायु प्रदूषण से बचाव करना होगा. इसके लिए डॉक्टरों ने कुछ टिप्स साझा किए हैं.

मौसम में परिवर्तन और ठंड शुरू होने के साथ ही दिल्ली और एनसीआर समेत कई इलाकों में वायु प्रदूषण के स्तर में इजाफा होने लगा है. बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप का पहला चरण भी शुरू करने का आदेश दिया गया है. प्रदूषण की वजह से सेहत पर भी गंभीर असर होता है. इससे लंग्स इंफेक्शन, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी हो जाती है. प्रदूषण का सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को होता है. डॉक्टरों का कहना है कि प्रेगनेट महिलाओं को अभी से उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में प्रदूषण का लेवल बढ़ेगा. अगर अभी से सावधानी बरती तो भविष्य में गंभीर खतरे से बचाव हो सकता है. गुरुग्राम के मैक्स हॉस्पिटल्स में एसोसिएट डायरेक्टर (ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी) और औरा स्पेशलिटी क्लीनिक की डायरेक्टर डॉ. रितु सेठी बताती हैं कि वायु प्रदूषण के बढ़ने की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियां होती हैं. जिन लोगों को पहले से ही सांस संबंधित बीमारियां हैं उनको अधिक खतरा रहता है. खासतौर पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बढ़ते प्रदूषण के कारण ज्यादा परेशानी होती है, हालांकि अभी प्रदूषण अधिक नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें इजाफा होगा. ऐसे में अभी से बचाव करना जरूरी है. प्रदूषण से बचाव नहीं किया तो गर्भवती महिला को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं.

बच्चों से लेकर बुजुर्ग झेल रहे प्रदूषण का दंश, प्रदूषण रोकने में नाकाम एजेंसियां; जमीनी हकीकत की रिपोर्ट

हर सुबह देश की राष्ट्रीय राजधानी स्मॉग की चादर से ढकी रहती है। वायु गुणवत्ता लगातार खराब से बेहद खराब और गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग वायु प्रदूषण का दंश झेलने का मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) तक हर दिन केंद्र व दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दे रहे हैं।

नई दिल्ली। हर सुबह देश की राष्ट्रीय राजधानी स्मॉग की चादर से ढकी रहती है। वायु गुणवत्ता लगातार खराब से बेहद खराब और गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग वायु प्रदूषण का दंश झेलने का मजबूर हैं।

सुप्रीम कोर्ट से लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) तक हर दिन केंद्र व दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दे रहे हैं। जमीन स्तर पर भले ही हालात नियंत्रण से बाहर हों, लेकिन विभिन्न एजेंसियों द्वारा एनजीटी में दाखिल की गई रिपोर्ट में आंकड़ों की कलाबाजी हैरान कर रही है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (DPCC) और दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा एनजीटी में दाखिल की गई रिपोर्ट में हर स्तर पर कार्रवाई के दावे किए गए हैं। वहीं, जमीनी स्तर पर हवाई साबित होती कार्रवाई को देखते हुए एनजीटी ने रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पेश है एक रिपोर्ट...

एमसीडी की रिपोर्ट खुले में आग जलाने पर रोक
512 सर्विलांस टीम का गठन किया गया है खुले में आग लगाने और अवैध स्थान पर सी एंड डी वेस्ट को डालने की निगरानी के लिए, इसमें 1,119 अधिकारी

हैं।

512 टीम में से 302 टीम व 560 अधिकारियों को विशेष रूप से खुले में बायोमास फायर की घटनाओं को दोशिएट में चेक करने की जिम्मेदारी दी गई है

191 चार्जिंग स्टेशन शुरू किए ई-मोबिलिटी बढ़ाने की दिशा में इलेक्ट्रानिक वाहनों के लिए और 17 स्टेशन का काम प्रगति पर है।

उल्लंघन करने वालों के चालान (अप्रैल से सितंबर 2023 तक एमसीडी की कार्रवाई)

100 चालान, 5.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया खुले में आग लगाने पर 76 चालान, 23 लाख का जुर्माना लगाया मलबा व विध्वंस कचरा डालने पर 2,37, 62,000 रुपये के 1,517 चालान काटे एमसीडी के बिल्डिंग विभाग ने

1.73 करोड़ रुपये के किए 815 चालान शीत सत्र में

सड़क पर पानी का छिड़काव

225 संप्रिंकल-एंटी स्माग गन की तैनाती एमसीडी ने की

1,900 किलोमीटर क्षेत्र में होता है पानी का छिड़काव

150 मैट्रिक टन धूल प्रति दिन मैकेनिकल रोड स्वीपर द्वारा एकत्रित करके निष्पारित जगह पर डंप की जाती है। एक हजार टन कचरे का नहीं होता है प्रबंधन

5 हजार टन प्रति दिन निर्माण व ध्वस्तीकरण से निकलता है कचरा

4 हजार टन कचरा के प्रबंधन का इंतजाम

1 हजार टन प्रतिदिन कचरा का प्रबंधन नहीं

एमसीडी की सड़क

15,582 किलोमीटर कालोनी सड़क कुल 57,500 कर्मचारियों की तैनाती

20 एंटी स्माग गन एमसीडी ने लगाई

15 एंटी स्माग गन ऊंची इमारतों पर लगाई

दिल्ली में 13 हाटस्पॉट

नरेला, बवाला, मुंडका, वजीरपुर, रोहिणी, आरके पुरम, ओखला,



जहांगीरपुरी, आनंद बिहार, विवेक बिहार, पंजाबी बाग, अशोक बिहार, द्वारका

एमसीडी ने लगाए पेड़ और झाड़ियां (अप्रैल से अक्टूबर 2023)

75,505 पेड़ और 2,21,338 झाड़ियां लगाई

2 लाख पेड़ व 3.25 लाख झाड़ियां लगाये दिया गया था लक्ष्य

दोबारा बनी या मरम्मत की गई सड़क (अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023)

214 किलोमीटर सड़क दोबारा बनाई गई

1.03 स्कवायर मीटर क्षेत्र में कुल 68,017 गड्ढों की मरम्मत की

डीपीसीसी की रिपोर्ट

कचरा जलाने के मामले पर कार्रवाई आठ नवंबर से 13 नवंबर के बीच

कुल निरीक्षण- 2,380

कूड़ा जलता मिला- 274

कुल चालान- 274 कुल जुर्माना- 2,55,000

जेनरेटर पर कार्रवाई

कुल निरीक्षण स्थल- 302

पाया गया इस्तेमाल- 0

निर्माण व ध्वस्तीकरण पर कार्रवाई (सितंबर से 13 नवंबर, 2023)

निरीक्षण के लिए गठित टीम -591

कुल निरीक्षण- 16,427

मौके पर मिला उल्लंघन-1,111

कुल जुर्माना- 229.65 लाख

सड़क की धूल को रोकने व नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था

संप्रिंकल-टैंकर - 375

एंटी-स्माग गन - 262

हाइड्रोजन इमारत पर पिछली साल

तैनात एंटी-स्माग गन-90

बड़े निर्माण स्थल पर तैनात एंटी-स्माग गन-233

पराली जलाने पर निगरानी के लिए कुल टीम -183

- पराली जलाने की एक भी घटना नहीं हुई दर्ज

औद्योगिक प्रदूषण पर कार्य

पाइप नेचुरल गैस में परिवर्तित

इंडस्ट्री-1,866

ईंधन से चलने वाली इंडस्ट्री-70

(जल्द ही पीएनजी में होगी परवर्तित)

दिल्ली के यातायात चौराहे पर वायु शोधन इकाइयां: 54

किस चौराहे पर कितनी इकाइयां

आईटीओ -14

आनंद बिहार-10

शादीपुर- 11

वजीरपुर चौक- 6

भीकाजी कामा प्लेस- 13

संवर्धन और शुद्धिकरण इकाई (वायूस) से एकत्र किया गया कुल पीएम-

1,20,551 परिचालन घंटे से 34.2 किलोग्राम है (पांच साइटों पर सभी उपकरणों का योग)

तीन स्थानों पर धूल

अक्टूबर-नवंबर 2018 के दौरान तीन चयनित स्थलों पर लागू किया गया धूल

दबाने का रसायन सराय काले खां सड़क (निर्माण स्थल)

नरेला पर डीडिए निर्माण स्थल (इमारत निर्माण)

पंजाब के 22 जिलों व हरियाणा के 11 जिलों में पराली जलाने की घटनाओं पर

नजर रखने के लिए सीएक्यूएम के समन्वय में सीपीसीबी के 33 विज्ञानियों का उड़नदस्ता तैनात किया गया

इसके अलावा औद्योगिक गतिविधियों से होने वाले वायु प्रदूषण से जुड़ी इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए 15 टीम का गठन किया गया है।

संजीवनी बूटी के बारे में कितना जानते हैं आप, यहां पढ़ें इससे जुड़ी नई जानकारीयां



अंकित सिंह

लंका से वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी का पता जरूर बताया था। लेकिन हनुमान जी वहां पहुंचने के बाद यह समझ नहीं पाए थे कि संजीवनी बूटी कौन है। यही कारण है कि वे पूरा पहाड़ लेकर लंका पहुंच चुके थे। सुषेण ने चार बूटियों को बेहद महत्वपूर्ण बताया था। इन 4 वोटरों में मृतसंजीवनी, विशालयाकर्णी, सुवर्णकरणी और संधानी बूटियां शामिल थीं। यह सभी हिमालय में ही मिलती थीं।

रामायण में जब लक्ष्मण इंद्रजीत के बाण से मूर्छित हुए थे तब हनुमान जी ने हिमालय की गोद से संजीवनी बूटी ले गए थे और इसके बाद लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। समय-समय पर इस संजीवनी बूटी की चर्चा होती है। दावा यह भी किया जाता है कि आज भी यह संजीवनी बूटी हिमालय की कई पहाड़ियों पर मौजूद है। कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान इकाई की ओर से यह दावा किया गया था कि द्रोणागिरी पहाड़ियों में रामायण के पौराणिक पौधे संजीवनी बूटी की ही तरह कुछ जड़ी बूटी मिले हैं। इसके बाद से उन बूटियों पर खोज लगातार जारी है। माना जाता है कि इन बूटियों में अद्भुत उपचार के गुण हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाने के लिए द्रोणागिरी ही आए थे। द्रोणागिरी फिलहाल उत्तराखंड में स्थित है और इसे पर्यटन के हिसाब से लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। द्रोणागिरी जोशीमठ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। द्रोणागिरी पर्वत के उस पार तिब्बत है। यही कारण है कि इसे भारत का आखरी छोड़ भी माना जाता है।

आज हम आपको इस संजीवनी बूटी के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं:-

बताया जाता है कि शक्राचार्य ने भगवान शिव से अमर होने का वरदान मांगा लेकिन भगवान शिव ने इसे अर्धभय करार दिया। हालांकि उन्होंने शक्राचार्य को संजीवनी विद्या के बारे में बता दिया। शक्राचार्य उस विद्या का इस्तेमाल करके युद्ध में मारे गए दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे।

संजीवनी के बारे में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो मृत्यु शैया पर है उसे यह स्वस्थ कर सकती है। संजीवनी चमत्कारी पौधा है जो कि हिमालय की गोद में ही प्राप्त होती है।

लंका से वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी का पता जरूर बताया था। लेकिन हनुमान जी वहां पहुंचने के बाद यह समझ नहीं पाए थे कि संजीवनी बूटी कौन है। यही कारण है कि वे पूरा पहाड़ लेकर लंका पहुंच चुके थे। सुषेण ने चार बूटियों को बेहद महत्वपूर्ण बताया था। इन 4 वोटरों में मृतसंजीवनी, विशालयाकर्णी, सुवर्णकरणी और संधानी बूटियां शामिल थीं। यह सभी हिमालय में ही मिलती थीं।

माना जाता है कि हिमालय की गोद में ऐसी कई बूटियां हैं जो कि स्वास्थ्य वर्धन में लाभदायक साबित होते हैं। इसी के अलावा संजीवनी भी चिकित्सा के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं।

संजीवनी का वैज्ञानिक नाम सेलाजिनेला ब्राह्मपेटेंसिस है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति लगभग 30 अरब वर्ष पहले कार्बोनiferस युग में हुई होगी। दवा तो यह भी किया जाता है कि संजीवनी संजीवनी मुरझाकर पपड़ी जैसी हो जाती है। इसके बावजूद भी वह जीवित रहती है और थोड़ी सी भी नमी मिलने के बाद खिल जाती है।

संजीवनी पत्थरों तथा शुष्क सतह पर भी उग सकती है। यह पौधा एक औषधि के रूप में काम करता है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को भी रेगुलेट करता है। आयुर्वेद में इसके औषधीय लाभों के बारे में वर्णन है।

आज भी वैज्ञानिक संजीवनी का सही तरीके से पता नहीं लगा पाते हैं। इसका कारण यह भी है कि जंगलों में ऐसे अनेक पौधे हैं जो कि एक ही समान के दिखते हैं। संजीवनी लंबाई की जगह सतह पर ज्यादा फैलती है।

इसके अलावा संजीवनी बूटी हार्ट अटैक, अनियमित मासिक धर्म, डिलीवरी के समय और जोडिस में भी लाभदायक साबित होता है।

वैज्ञानिक यह भी दावा करते हैं कि संजीवनी बूटी वाली कहानी त्रेता युग की है जिसमें सदियों बीत गई हैं। आजकल तो 1-2 सालों में भी चीजे तेजी से बदल सकती है। ऐसे में संजीवनी बूटी में भी अंतर आया होगा। आज वह हल्के रंग में हम सबके बीच जरूर होगी।

दावा तो यह भी किया जाता है कि संजीवनी बूटी श्रीलंका में भी मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हनुमान जी जिस पहाड़ को उठाकर से लंका पहुंचे थे उसका एक टुकड़ा रीतिगाला में भी गिरा था। रीतिगाला में आज भी ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं लेकिन संजीवनी से बेहद अलग है।

अधेड़ उम्र की महिलाओं में वायु प्रदूषण के असर के कारण वे मोटी (Obese) होती जा रही हैं. (तस्वीर: Wikimedia Commons) अधेड़ उम्र की महिलाओं में वायु प्रदूषण के असर के कारण वे मोटी (Obese) होती जा रही हैं.

मोटापा एक वृहद वैश्विक समस्या होती जा रही है. बेशक यह कोई रोग नहीं हैं लेकिन आज के दौर में यह एक साथ कई बीमारियों (Disease) के होने की वजह बन जाता है. मोटापा लाइफस्टाइल की कई खामियों के होने का संकेतक भर है, जो कि अस्वस्थ खुराक, कसरत की कमी, अनुवांशिकी या फिर इन सभी समस्याओं का होना बताता है. लेकिन क्या पर्यावरण में कोई ऐसा कारक है जिसका मोटापे से संबंध. अगर नए अध्ययन की माने तो वायुप्रदूषण (Air Pollution) और महिलाओं में अधिक वजन के बीच में एक संबंध है. जो कि साधारण लोगों के लिए ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए भी एक चौंकाने वाला नतीजा है.

50 साल के आसपास की उम्र की महिलाएं

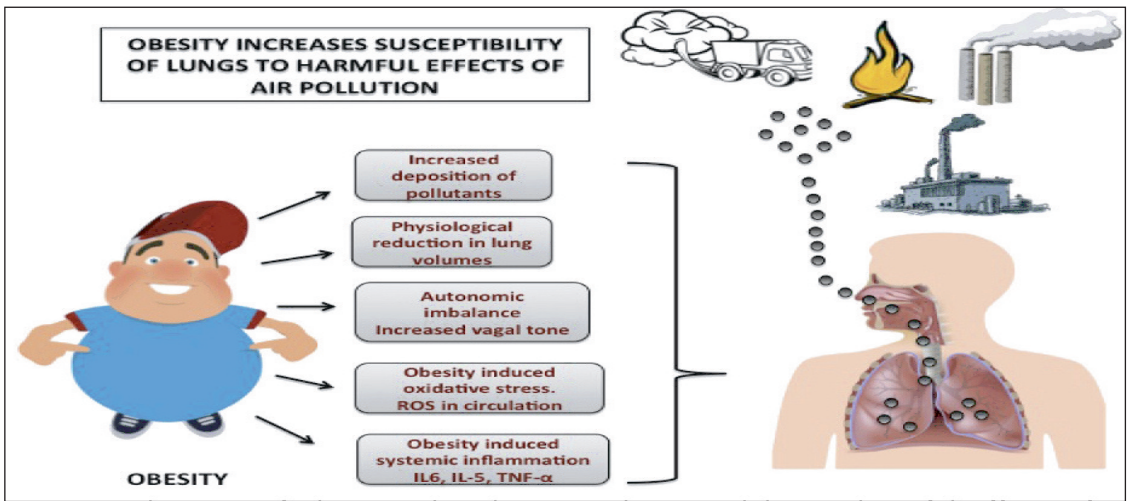
यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के शोधकर्ताओं ने अपने नए अध्ययन में इस अप्रत्याशित संबंध की खोज है. इस अध्ययन के प्रथम लेखक जिन वांग के मुताबिक उम्र के 40 और 50 साल के दशक में पहुंच चुकीं जो महिलाएं वायुप्रदूषण का लंबे समय से सामना कर रही हैं, जिससे उनका शारीरिक भार अनुपात, कमर का आकार और शरीर का फैट बढ़ने लगता है. जिस वजह से उन्हें सेहत संबंधी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

वायुमंडलीय प्रदूषकों से गहरा नाता

इन नकारात्मक प्रभावों का नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और उच्च स्तर के महीन कणों से विशेष संबंध है जो प्रमुख वायु प्रदूषक के तौर पर जाने जाते हैं. शोधकर्ताओं ने लिखा है कि इस अध्ययन में उन्होंने अमेरिका की 1654 श्वेत, अश्वेत, चीनी और जापानी महिलाओं को शामिल किया था जिनकी औसत उम्र साल 2000 से 2008 के बीच में 49.6 साल थी.

शरीर संरचना के मापन

शोधकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने प्रतिभागियों के रियायशी पतों के आधार पर उन के इलाकों के वायु प्रदूषण की मात्रा से जोड़ा.



कई कारकों में बदलाव

इस अध्ययन के नतीजों के विश्लेषणों ने दर्शाया कि वायु प्रदूषण के संपर्क में आने का संबंध शरीर में ज्यादा फैट, उच्च अनुपात फैट, और मध्य उम्र की महिलाओं में निम्न कमजोर भार से है. जैसे इसमें से शरीर का फैट 45 प्रतिशत यानि करीब 2.6 पाउंड या 1.18 किलोग्राम तक बढ़ा पाया गया था. इसी तरह के नतीजे बाकी कारकों में भी देखने को मिले.

वायु प्रदूषण (Air Pollution) से वजन बढ़ने, शरीर का आकार बढ़ने जैसे कई कारक तत्व प्रभावित होते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

शारीरिक गतिविधि

इसके अलावा शोधकर्ताओं ने शरीर संरचना के लिए लिहाज से वायु प्रदूषण और शारीरिक गतिविधि के बीच संबंध की भी पड़ताल की. उन्होंने पाया कि उच्च स्तर की शारीरिक गतिविधि प्रभावी रूप से शारीरिक संरचना के बदलावों को कम कर सकती है जिनका संबंध वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से है.

यह अध्ययन डाइबिटीज केयर में प्रकाशित हुआ है. इस शोध में वांग ने समझाया कि चूँकि इस अध्ययन ने मध्य उम्र की महिलाओं को लक्षित किया था, इसलिए इस अध्ययन की पड़ताल के नतीजों को पुरुषों और दूरी उम्र की महिलाओं के लिए समान्य रूप से लागू नहीं होता है.

देशभर के घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, आस्था के नाम की लगाई डुबकी

परिवहन विशेष न्यूज

सनातन धर्म में हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा का अपना एक महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा विशेष मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए कार्तिक मास को उत्तम बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने से बड़े-बड़े यज्ञों को करने के बराबर फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा पर भक्तों ने गंगा, सरयू और गोमती नदी में डुबकी लगाई। हरिद्वार से लेकर गढ़मुक्तेश्वर और अयोध्या-वाराणसी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। जिन्होंने स्नान किया।

गङ्गामुक्तेश्वर खादर क्षेत्र में लगने वाले ऐतिहासिक और पौराणिक कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले में दीपदान पर्व पर 25 लाख श्रद्धालुओं ने पड़ाव डालकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सड़कों पर वाहनों के संख्या बढ़ने के कारण लाखों श्रद्धालुओं को गंगा मेले तक पैदल सफर करना पड़ा।

बता दें कि ब्रजघाट के तट पर रविवार को शाम तक 25 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए गंगा भक्तों का आगमन लगातार जारी है। जिससे मेले में भीड़ के साथ ही रौतक भी बढ़ती जा रही है। गंगा में स्नान के साथ ही अठखेलियां करते हुए भक्त हर-हर गंगे का जयघोष कर रहे हैं।

तट समेत चारों तरफ भगवान सत्यनारायण की कथा, हवन और पूजन हो रहा है। जिससे कार्तिक पूर्णिमा मेला स्थल का वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा है। दीपदान पर्व पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने से मेला मार्ग, गढ़-चौपाला समेत अन्य संपर्क मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से गंगा तट तक जाने के लिए पैदल चलना पड़ा।

कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर संगम पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा-यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया।



इसके बाद दीपदान कर मां गंगा की आरती उतारी गई। आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान हो रहा है। भक्तों ने गंगा, सरयू और गोमती नदी में डुबकी लगाई। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। पूर्णिमा, रविवार की रात से ही लगाई गई है। इसलिफ स्नान कल से ही शुरू हो गए। वहीं हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर उत्तम दृश्य देखने को मिला।

घाट पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से व्यापक बंदोबस्त किया गया था। पुलिस बल के साथ महिला पुलिसकर्मियों की भी इयूटी लगाई गई थी। रात के वकत गढ़ आने वालों की सड़क पर भीड़

लग गई। संगम सहित बलुआ घाट, काशीराज घाट, नागवासुकि, रामधाम, काली घाट, सरस्वती घाट, काला घाट, वीआईपी घाट, महावीर घाट सहित गंगापार के श्रृंगवेरपुर, फाफामऊ, नवरागंज, झुंसी के अलावा यमुना नगर के नैनी, अरैल आदि घाटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया।

प्रयागराज में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्थित श्रीबंदे हनुमानजी का दर्शन पूजन किया। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को लंबी कतार लगी रही। भंडिर पक्षिर में भंडारे के साथ ही सुंदरकांड और अखंड रामायण श्रीरक्षीकीर्तन



सहित अन्य अनुष्ठान चल रहे हैं। दर्शन पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके अलावा भगवान शिव, रामजानकी सहित अन्य मंदिरों में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। रामघाट पर स्थित रामजानकी मंदिर के अलावा काली मंदिर आदि में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया।

बरेली में कार्तिक पूर्णिमा पर सोमवार को रामगंगा के घाटों पर श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा। चौबारी मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। तड़के के बाद बजे से ही स्थान का सैलाबिला शुरू हो गया। हर-हर गंगे से घाट गुंज उठा। चौबारी घाट पर



स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशान न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रविवार को भी घाटों की साफ-सफाई को अंतिम रूप देने का काम चलता रहा।

कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। धर्मनगरी में एक दिन पहले ही होटल, लॉज और धर्मशाला पैक हो गए थे। रविवार सुबह भी लाखों की संख्या में लोगों ने गंगा स्नान कर पुण्य लाभ कमाया। शक्तिपीठों में सभी ने दर्शन किए और देर शाम आरती में शामिल होकर मां गंगा से मनोवांछित

फल की कामना की। रविवार और सोमवार को अवकाश के चलते दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल और अन्य जगहों से लोग शनिवार शाम से ही हरिद्वार पहुंचने लगे थे।

कार्तिक पूर्णिमा के चलते हरिद्वार में उमड़ी
भीड़ से वाहनों का रेला लगा हुआ है। शहर की
गलियाँ और कूँचे तक जाम की चपेट में आ गए
सबसे अधिक परेशानी नजीबाबाद हाईवे और
चंडीघाट चौक से देहरादून मार्ग पर हुई। वाहनों
लंबी कतार के चलते अधिकांश लोग परेशान
दिखे।



जंगल में मिला युवक का शव, अभी तक
नहीं हो पाई है शिनाख्त; पुलिस जल्द
करेगी खुलासा

सिंभावली में हरोड़ा गांव के जंगल में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। घटना का जल्द पर्दाफाश किया जाएगा।

थाना क्षेत्र के गांव हरौड़ा में स्थित एक ईख के खेतों में अज्ञात युवक का शव मिला है। शवना मिलने पर काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस मौके पर शवना खिलाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। ईखवाली थाना पुलिस के अनुसार, संभवतः मौके का सुबह कुछ किसान खेतों में कार्य करने के लिए गए थे। तभी ईख के खेतों के बीच बनी नाली में एक युवक का शव पड़ा मिला। इससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। शवना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से मुक्त की शवना खिलाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी है। ईखवाली थाना प्रभारी धर्मदेव सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का कारण पता चल सकेगा। उन्होंने बताया कि आसपास के थानों को शव मिलने की सूचना दे दी गई है। प्रत्यक्ष जांच किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मृतक की शवना खिली हो सके। घटना का जल्द पर्दाफाश किया जाएगा।

पिलखुवा से जुड़े ISI के तार: वेल्डर के बैंक खाते में आए थे 70 लाख, पाकिस्तान के अलावा यहां से ट्रांसफर हुई रकम

पिलखुवा के फरीदनगर निवासी वेल्डर के बैंक खाते में 70 लाख रुपये आए थे। पाकिस्तान के अलावा पंजाब से भी रकम ट्रांसफर की गई थी। वेल्डर के आईएसआई से संबंध की खबर से कस्बे के लोग सकते में है। वेल्डर लंबे समय से सुरक्षा एजेंसी की रडार पर था। एटीएस ने 15 दिन पूर्व भी वेल्डर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था।

आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारतीय सेना की जासूसी करने के आरोप में कब्जा फरिदनगर निवासी वेल्डर रियाजुद्दीन को गिरफ्तार किया है। रियाजुद्दीन लगभग दस साल से पिथुखुवा में रह रहा था। वेल्डर के बैंक खाते में 70 लाख रुपये आए थे। पाकिस्तान के अलावा पंजाब से भी रकम ट्रांसफर की गई थी। वेल्डर को आईएसआई से संबंध की खबर से कब्जे के लोग सन्तुष्ट में हैं। वेल्डर लंबे समय से सुरक्षा एजेंसी की छ्दार पर था। एटीएस ने 15 दिन पूर्व भी वेल्डर को पृष्ठताछ के लिए हिरासत में लिया था।

इसके बाद एटीएस ने वेल्डर को छोड़ दिया था। वेल्डर रियाजुद्दीन के पिता अनवर सैफी ने बताया कि एटीएस बोते 18 नवंबर को पिल्लुखवा पहुंची थी और वहां से रियाजुद्दीन का मोबाइल फोन ले गई। इसके बाद एटीएस ने 22 नवंबर को रियाजुद्दीन को नोएडा से उठा लिया। पृष्ठताछ में बताया कि उसे जांच के लिए रखनऊ ले जाया रहा है। मौफिया द्वारा रविवार को रियाजुद्दीन की गिरफ्तारी की खबर लगी।

रियाजुद्दीन के खाते में आए थे 70 लाख रुपये

सुरक्षा एजेंसी को पता लगा कि रियाजुद्दीन के फोर-द-नगर स्थित केनारा बैंक खाते में मार्च 2022 से अप्रैल 2023 तक 76 लाख रुपये आए हैं। केनारा प्रॉक्सिमिटी के अलावा पंजाब बैंक भी ट्रॉसपर करी गई थी। रियाजुद्दीन रिकमर बैंक के अलावा दो अन्य बैंकों में भी खातों की जानकारी लगी थी। खाते का संचालन बिहार के पश्चिमी चंपारण निवासी इजहारूल हुसैन कर रहा था। जांच में सामने आया था कि रियाजुद्दीन को लाखों रुपये खाते का किराया मिलता था। राजस्थान के नीमनगर में काम दौरान हुसैन थी वेल्टर रियाजुद्दीन और कारीगर इजहारूल की दोस्ती।

पिता अनवर के अनुसार, अपने अपने तनों बेटों 40 वर्षीय रियाजुद्दीन, शहजाद और सफरजाद के साथ लगभग दस साल पहले राजस्थान के नीमनगर में एक कंपनी में काम करने गए थे। बिहार निवासी इजहारूल वहां पत्थर पिसाई का कारीगर था। वहीं पर रियाजुद्दीन और इजहारूल की पहचान हुई और कुछ ही समय में दोनों गहरे दोस्त बन गए। एटीएफ के अनुसार इजहारूल को पहल ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वह इस समय बिहार की बैतिया जेल में बंद है।

दस साल से परिवार सहित पिलखुवा में रह रहा है रियाजुद्दीन पिता बनकर के अनुसार, रियाजुद्दीन विवाहित है और उसके चार बच्चे हैं। अनवर ने बताया कि रियाजुद्दीन साल 2014 के बाद अपने परिवार को लेकर पिलखुवा चला गया और वहीं सद्दीकनगर कोलांनी में मकान बनाकर रह रहा है रियाजुद्दीन फरीदनगर बहुत कम आता था।

नेतिक मूल्यों में गिरावट को देखते हुए आज वैदिक शिक्षा को औपचारिक रूप से शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाए जाने की जरूरत है। यह शाश्वत सत्य है कि वैदिक शिक्षा के व्यावहारिक उद्देश्य रहे हैं, जिनकी आज बहुत जरूरत है। इनमें चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, कार्यक्षमता और नागरिक जिम्मेदारी का विकास और विरासत व संस्कृति का संरक्षण शामिल हैं। नई शिक्षा नीति-2020 में इन बिन्दुओं पर व्यापक ध्यान दिया गया है। हमारे छात्रों को शानदार शिक्षा परंपराओं को आत्मसात करने में और अधिक सक्षम बनाने के लिए वैदिक और सांस्कृतिक शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यूं भी वैदिक शिक्षा सुशासन के सिद्धांतों का स्टोर हाऊस है। इन सिद्धांतों को शिक्षा में जोड़ कर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया जा सकता है।

वैदिक ज्ञान भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है, लेकिन आज की नई बौद्धिक ज्ञान की शिक्षा प्रणाली में समुचित स्थान नहीं मिल पाया है जिसका शिक्षा समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। खबरों के अनुसार हाल ही में वेदों की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए की परियोजनाएँ बनाई गई हैं। यह धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के मुताबिक इसका उपयोग भारतीय भाषाओं और वेदों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए किया जाएगा। वेद और भारतीय भाषाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएँ इसी माह से शुरू की जा रही हैं। गौरतलब है कि वैदिक शिक्षा पर आधारित बोर्ड से दसवीं और बारहवीं कक्षा पास करने वाले छात्र अगले उच्च शिक्षा के लिए किसी भी कॉलेज में दाखिला लेने के पात्र होंगे। इसमें मेंडल और इंजीनियरिंग जैसे उच्च शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं।

यानी वैदिक बोर्ड से दसवीं और बारहवीं कक्षा पास करने वाले छात्र एमबीबीएस और इंजीनियरिंग समेत किसी भी कॉलेज में तय क्राइटेरिया के अनुसार आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। यह महत्वपूर्ण नियम सरकार द्वारा नामित निकाय, एप्सोएएनएन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) द्वारा लिए गए निर्णय पर आधारित हैं। वैदिक शिक्षा सांस्कृतिक दृष्टि पर बल देती थी।

इसके मुनाबिक शिक्षित व्यक्ति को साहित्य, कला, संगीत आदि की समझ होनी चाहिए, उसे जीवन के उच्च आदर्शों का ज्ञान भी होना चाहिए। पूर्वजों की परंपरा और संस्कृति की रक्षा शिक्षित व्यक्ति का कर्त्तव्य था। वैदिक शिक्षा से समस्त देश में कुछ ऐसे आधारभूत मूल्यों की स्थापना हुई जो आज भी सांस्कृतिक एकता के आधार हैं। कुछ लोगों के अनुसार आज की शिक्षा प्रणाली में यह



एक आऊटेस्टेड विचार समझा जा सकता है। वैदिक शिक्षा प्रणाली के अनेक गुण थे। इन गुणों का तत्व आज भी प्रासंगिक है। वैदिककालीन शिक्षा निःशुल्क थी, गुरुकुल में शिक्षों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। उनके अवसर, वस्तु तथा भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क होती थी। वैदिक काल की शिक्षा पर होने वाले व्यय की पूर्ति शासन, नाह्य लोगों तथा विश्वामित्र एवं गुरु दक्षिणा से की जाती थी। वैदिककालीन शिक्षा द्वारा मनुष्यों का शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक तथा आध्यात्मिक विकास किया जाता था। वैदिककालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक था। वैदिक काल में मनुष्यों के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता था और इसके लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को सम्मिलित किया जाता था। हमारी आज की शिक्षा में आध्यात्मिक तत्व न होने के कारण हमारे दिलों-दिमाग से सामाजिक संवेदना विलुप्त होती जा रही है। वैदिककालीन शिक्षा में उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। अनुकरण, व्याख्यान, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तर, तर्क, विचार-विमर्श, निवेदन-मनन, सिद्धिध्यासन, प्रयोग, नाटक एवं कहानी इत्यादि वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक विधियों का विकास किया जा चुका था। इनको पुनः हमारे शिक्षण में शामिल करने की जरूरत है। वैदिक काल में गुरु तथा शिष्यों का जीवन अत्यंत संयमित और अनुशासित होता था। उनकी जीवनशैली सादा जीवन व उच्च विचार पर आधारित थी। वैदिककालीन शिक्षा में गुरु तथा शिष्यों के मध्य मधुर संबंध थे। दोनों के मध्य स्नेह तथा ब्रह्मा का संबंध था।

दोनों एक-दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखते थे तथा शिक्षकों के बीच मानस पिता-पुत्र के संबंध थे। क्या आज ऐसे रिश्ते वांछित नहीं हैं? वैदिककालीन शिक्षा में गुरुकुलों का पर्यावरण अति उत्तम था। गुरुकुल प्रकृति के स्वच्छ वातावरण से युक्त स्थलों में होते थे, जहां जन

दोनों एक-दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखते थे तथा शिक्षकों के बीच मानस पिता-पुत्र के संबंध थे। क्या आज ऐसे रिश्ते वांछित नहीं हैं? वैदिककालीन शिक्षा में गुरुकुलों का पर्यावरण अति उत्तम था। गुरुकुल प्रकृति के स्वच्छ वातावरण से युक्त स्थलों में होते थे, जहां जन कोलाहल नहीं था तथा जल और वायु शुद्ध प्राप्त होती थी। आज हम छात्रों को किन हालात में शिक्षित कर रहे हैं? वस्तुतः मशीनों के जरिए दी जा रही शिक्षा मनुष्य रूपी छात्रों को असंवेदनशील रोबोट के रूप में विकसित कर रही है यहां पर सांस्कृतिक शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है।

कोलाहल नहीं था तथा जल और वायु शुद्ध प्राप्त होती थी। आज हम छात्रों को किन हालात में शिक्षित कर रहे हैं ? वस्तुतः मशीनों के जरिए दी जा रही शिक्षा मनुष्य रूपी छात्रों को असेवेनकालीन शोषाढ के रूप में विकसित कर रही है। यहां पर सांस्कृतिक शिक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैदिक शिक्षाप्राली जीवन पद्धति संस्कृत प्राणी थी। वैदिक शिक्षाप्राली पूर्णतया दोष रहित थी, ऐसा कहना कठिन है, वैदिककालीन शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था उत्तरदायित्व नहीं था। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः व्यक्तिगत नियंत्रण में थी, जो पूर्णतः गुरुकुलों तक सीमित थी। अतः इससे जनशिक्षा की अवहेलना होती थी। वैदिककालीन शिक्षा में आयु की संरक्षितता एवं विधिवत व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि

वैदिककालीन शिक्षा का व्यय राजा, धनी लोग, भिक्षाटन तथा गुरु दक्षिणा से पूरा किया जाता था, किन्तु इस सबका कोई निश्चित समय, मात्रा के न होने से असमंजस की स्थिति रहती थी। वैदिक जमाने की तरफ आज भी अमरीका और अनेक देशों में उच्च शिक्षा संस्थाओं की निर्रक्त फंडिंग अमीर लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहां की स्थिति दयनीय है। वैदिककालीन शिक्षा में रटने पर विशेष बल दिया जाता था।

यद्यपि उस समय उत्तम शिक्षा विधियों का विकास हो चुका था, किंतु लिखने की समुचित व्यवस्था ही अभाव होने के कारण यहां रसने पर विरोध बल दिया जाता था। वैदिककालीन शिक्षा की अनुशासन व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। स्वामी दयानंद जी, महामात्स्य हंसराज जी व महात्मा आनंद स्वामी जी इत्यादि अनेक वैदिक कर्मयोगियों से प्रेरित पूरे देश में कार्यरत डीएवी व आर. समाज से जुड़ी संस्थाएं वैदिक परचम की शिक्षा के जरूर गतिशील रसने के लिए इस समय डॉ. पूनम सूजी (पदमशील अलंकृत) के, के नेतृत्व में निरंतर अच्छे काम कर रही हैं। वे लिखित मूल्यों में परिगठित को देखते हुए आज वैदिक शिक्षा को औपचारिक रूप से शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाए जाने की जरूरत है। यह शास्त्र सत्य है कि वैदिक शिक्षा के व्यावहारिक उद्देश्य रहे हैं, जिनकी आज बहुत जरूरत है। इनमें चित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, कार्यक्षमता और नागरिक जिम्मेदारी का विकास और विरासत से संस्कृत का संरक्षण शामिल हैं। नई शिक्षा नीति-2020 में इन बिन्दुओं पर व्यापक ध्यान दिया गया है। हमारे छात्रों व शानदार शिक्षा परंपराओं को आत्मसात करने में और अधिक सक्षम बनाने के लिए वैदिक और सांस्कृतिक शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। यू थी वैदिक शिक्षा सुशासन के सिद्धांतों का स्टोर हाउस है। इन सिद्धांतों को शिक्षा में जोड़ कर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। अतः समाज में नैतिकता की स्थापना के लिए वैदिक शिक्षा जरूरी है।

डॉ. वरिंदर भाटिया

स्कोडा ने स्लाविया और कुशाक का नया वेरिएंट किया लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत



चेक ऑटो दिग्गज ने Skoda ने अपने दो फ्लैगशिप प्रोडक्ट Slavia और Kushaq के नया वेरिएंट पेश किया है। स्कोडा कुशाक और स्लाविया पहले से ही स्टैंडर्ड वेरिएंट के अलावा कई विशेष संस्करण संस्करणों के साथ पेश किए गए हैं। इसके चार वेरिएंट हैं जो मानक के अलावा पेश किए गए हैं। इनमें लावा ब्लू मैट संस्करण मोटे कार्लो और ओनिक्स संस्करण शामिल हैं।

नई दिल्ली। चेक ऑटो दिग्गज ने Skoda ने अपने दो फ्लैगशिप प्रोडक्ट Slavia और Kushaq के नया वेरिएंट पेश किया है। इसे Elegance नाम दिया गया है, जो मूल रूप से इन दोनों मॉडलों का एक नया ब्लैक एडिशन है। Skoda ने Kushaq Elegance को 18.31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जो ऑटोमैटिक वर्जन के लिए 19.51 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, Slavia Elegance को 17.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया है और इसके ऑटोमैटिक वर्जन की कीमत 18.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

Elegance Edition में क्या खास ?
स्कोडा ने कुशाक एसयूवी और स्लाविया सेडान दोनों को ऑल-ब्लैक थीम में पेश किया है। कुशाक एलिंगेंस और स्लाविया एलिंगेंस वेरिएंट कुछ कॉस्मेटिक अपडेट के साथ आएंगे, जो इसे मौजूदा वर्जन से अलग बनाते हैं। इनमें नए डुअल-टोन अलॉय व्हील, ग्रिल पर क्रोम गार्निश, स्टीयरिंग व्हील के साथ-साथ बी-पिलर पर एलिंगेंस बैजिंग आदि शामिल हैं। हुड के तहत, दोनों मॉडल स्कोडा के 1.5-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होंगे। कुशाक और स्लाविया एलिंगेंस संस्करण मैनुअल और डीएसजी ट्रांसमिशन दोनों विकल्पों के साथ आएंगे।

Slavia और Kushaq को

मिलते हैं कई एडिशन
स्कोडा कुशाक और स्लाविया पहले से ही स्टैंडर्ड वेरिएंट के अलावा कई विशेष संस्करण संस्करणों के साथ पेश किए गए हैं। इसके चार वेरिएंट हैं, जो मानक के अलावा पेश किए गए हैं। इनमें लावा ब्लू, मैट संस्करण, मोटे कार्लो और ओनिक्स संस्करण शामिल हैं। लॉन्च होने वाला कुशाक और स्लाविया का आखिरी वेरिएंट ओनिक्स संस्करण और एम्बिशन प्लस था, जिसे इस साल की शुरुआत में त्योहारी अवधि के दौरान पेश किया गया था। सितंबर में लॉन्च किया गया, कुशाक ओनिक्सप्लस वेरिएंट 11.59 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर आता है और इसे एसयूवी के एंट्री-लेवल संस्करण से एक ऊपर रखा गया है। 1.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित, ये संस्करण नए 16-इंच के अलॉय व्हील, विंडो, ग्रिल और टेलगेट पर क्रोम इंस्टेंट जैसे कॉस्मेटिक अपडेट के साथ आता है। सितंबर में लॉन्च की गई स्लाविया एम्बिशन प्लस को 12.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है। मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध, टॉप-एंड संस्करण की कीमत 13.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। स्लाविया एम्बिशन प्लस संस्करण में भी समान कॉस्मेटिक अपडेट मिलते हैं, जिनमें ज्यादातर क्रोम गार्निश शामिल हैं। हुड के तहत, ये 1.0-लीटर टीएसआई पेट्रोल यूनिट के साथ आती है।

Maruti Suzuki की गाड़ियों को सस्ते में खरीदने का आखिरी मौका ! इस दिन से बढ़ जाएंगे सभी मॉडलों के दाम

Maruti Suzuki अपने सभी मॉडलों की कीमत बढ़ाने जा रही है। मारुति सुजुकी ने कहा है कि कार की कीमतों में नवीनतम बढ़ोतरी बढ़ती उत्पादन लागत के कारण लागू की जाएगी। कंपनी द्वारा बढ़ाई जाने वाली नई कीमतें अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगी। हालांकि Maruti Suzuki ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या नई प्राइस हाइक कंपनी के सभी मॉडलों पर लागू होगी या फिर नहीं?

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki अपने सभी मॉडलों की कीमत बढ़ाने जा रही है। यदि आप जल्द ही मारुति सुजुकी कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके पास इसे महंगा होने से पहले घर चलाने के लिए सिर्फ एक महीने का समय बचा है। कंपनी ने आज यानी 27 नवंबर को घोषणा की है कि वह नए साल से अपने मॉडलों की कीमत में बढ़ोतरी करेगी।

कब बढ़ेंगी कीमतें ?
मारुति सुजुकी ने कहा है कि कार की कीमतों में नवीनतम बढ़ोतरी बढ़ती उत्पादन लागत के कारण लागू की जाएगी। कंपनी द्वारा बढ़ाई जाने वाली नई कीमतें अगले साल 1 जनवरी से लागू होंगी। हालांकि, Maruti Suzuki ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या नई प्राइस हाइक कंपनी के सभी मॉडलों पर लागू होगी या फिर नहीं ?

कंपनी ने क्या कहा ?
सोमवार को मारुति सुजुकी की एक नियामक फाइलिंग में कहा गया कि कुल मुद्रास्फीति और कर्मांडिटी की कीमतों में वृद्धि और लागत में वृद्धि के

कारण बढ़ोतरी आवश्यक हो गई है। हालांकि, कार निर्माता ने आश्वासन दिया कि वह खरीदारों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठा रही है। इसमें कहा गया है, इहालांकि कंपनी लागत कम करने और वृद्धि की भरपाई करने के लिए अधिकतम प्रयास करती है, लेकिन उसे कुछ वृद्धि का भार बाजार पर डालना पड़ सकता है। यह मूल्य वृद्धि विभिन्न मॉडलों में अलग-अलग होगी।

कितने बढ़ेंगे दाम ?
मारुति सुजुकी ने प्रस्तावित मूल्य वृद्धि की मात्रा निर्दिष्ट नहीं की है। कार निर्माता वर्तमान में छोटी से मध्यम आकार की कारें बेचता है, जिनमें से कुछ कॉम्पैक्ट या बड़े सेगमेंट में हैं। ऑल्टो, इसका एंट्री-लेवल मॉडल और साथ ही इसके लाइनअप की सबसे छोटी कार 3.54 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर आती है। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस पर आधारित इनविक्टो एमपीवी, मारुति द्वारा बेची जाने वाली सबसे बड़ी कार है। इनविक्टो की कीमत 24.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।



सिंपल डॉट वन इलेक्ट्रिक स्कूटर इस दिन होगा लॉन्च, कंपनी ने बताई प्री-बुकिंग शुरू होने की तारीख

Simple Energy ने सोमवार को घोषणा की है कि वह 15 दिसंबर को भारतीय बाजार में अपना Simple Dot One इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी। Simple Dot One अपने प्लेटफॉर्म को सिंपल वन के साथ साझा करेगा और इसमें एक निश्चित 3.7 kWh की बैटरी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि मॉडल की प्रमाणित रेंज 151 किलोमीटर है और इसे विशेष रूप से तैयार किए गए टायर दिए गए हैं, जो इसकी ऑन-रोड रेंज को बढ़ाते हैं। इसके अलावा, मॉडल में अन्य हाइलाइट्स के अलावा 30 लीटर अंडर-सीट स्टोरेज एरिया, टचस्क्रीन इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर और ऐप कनेक्टिविटी के लिए सपोर्ट मिलेगा। सिंपल डॉट वन मॉडल की डिलीवरी जनवरी 2024 से शुरू होगी। इससे संबंधित बहुत सी आधिकारिक जानकारी आना अभी बाकी है।

सिंपल एनर्जी के फाउंडर और सीईओ सुहास राजकुमार ने कहा-
आज सिंपल एनर्जी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा है क्योंकि हम गर्व से सिंपल डॉट वन पेश कर रहे हैं, जो हमारी अग्रणी सिंपल वन सीरीज का नवीनतम किराया टी एडीशन है। सुलभ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रदान करने का हमारा दृष्टिकोण सिंपल डॉट वन में परिवर्तित होता है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आकर्षक डिजाइन का मिश्रण है। हम अपने सम्मानित ग्राहकों के अटूट समर्थन पर धरोसा करते हुए इसके बाजार में लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

पहले) थी। Simple Dot One अपने प्लेटफॉर्म को सिंपल वन के साथ साझा करेगा और इसमें एक निश्चित 3.7 kWh की बैटरी मिलेगी। कंपनी का दावा है कि मॉडल की प्रमाणित रेंज 151 किलोमीटर है और इसे विशेष रूप से तैयार किए गए टायर दिए गए हैं, जो इसकी ऑन-रोड रेंज को बढ़ाते हैं। इसके अलावा, मॉडल में अन्य हाइलाइट्स के अलावा 30 लीटर अंडर-सीट स्टोरेज एरिया, टचस्क्रीन इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर और ऐप कनेक्टिविटी के लिए सपोर्ट मिलेगा। सिंपल डॉट वन मॉडल की डिलीवरी जनवरी 2024 से शुरू होगी। इससे संबंधित बहुत सी आधिकारिक जानकारी आना अभी बाकी है।

सिंपल एनर्जी के फाउंडर और सीईओ सुहास राजकुमार ने कहा-
आज सिंपल एनर्जी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा है क्योंकि हम गर्व से सिंपल डॉट वन पेश कर रहे हैं, जो हमारी अग्रणी सिंपल वन सीरीज का नवीनतम किराया टी एडीशन है। सुलभ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रदान करने का हमारा दृष्टिकोण सिंपल डॉट वन में परिवर्तित होता है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आकर्षक डिजाइन का मिश्रण है। हम अपने सम्मानित ग्राहकों के अटूट समर्थन पर धरोसा करते हुए इसके बाजार में लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।



गरीबी घटी, आय असमानता भी घटे


डा. जयंती लाल भंडारी

हाल ही में केंद्र सरकार ने 80 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की योजना आगामी पांच वर्षों यानी दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक गरीबों के सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की जरूरत बनी हुई है। पिछले पांच वर्षों में 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ऐसे में पूरे देश के गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। निःसंदेह मुफ्त खाद्यान्न योजना की जरूरत न केवल गरीबों के सशक्तिकरण के लिए, वरन आय असमानता घटाने के लिए आवश्यक बन चुकी हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में हाल ही में 6 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गरीबी 2015-2016 के मुकाबले 2019-2021 के दौरान 25 फीसदी से घटकर 15 फीसदी आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि गरीबी निवारण अभियान से भारत में गरीबी घटी है, लेकिन अभी भी भारत में आय की असमानता बढ़ी हुई है। यह उल्लेखनीय है कि एशिया पैसेफिक ह्यूमन डेवलेपमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 में जहां करीब 37 हजार रुपए थी, वहीं वर्ष 2022 में बढ़कर करीब 2 लाख रुपए हो गई है। गौरतलब है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित हुआ है। इसका उद्देश्य नागरिकों की गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की 5 किलोग्राम मात्रा उपलब्ध कराना है। ऐसे में इसके तहत राशन कार्डधारकों को चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए और नई अनाज 1 रुपए प्रति किलो वितरण की शुरुआत की गई।

कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब

कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त अनाज दिए जाने की भी शुरुआत की। कई बार इसकी अवधि बढ़ाने के बाद सरकार ने एक जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज वितरण की योजना में मिलाने का निर्णय किया। सरकार ने चावल और गेहूं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत क्रमशः तीन रुपए और दो रुपए प्रति किलो की दर से बेचने के बजाय मुफ्त कर दिया। अब वर्ष 2028 तक एक बार फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाली देश की दो-तिहाई आबादी को राशन प्रणाली के तहत मुफ्त में अनाज देने की भारत की पहल दुनिया भर में रेखांकित की जा रही है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष सहित दुनिया के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा के वैश्विक संगठनों के द्वारा भारत की खाद्य सुरक्षा की जोरदार सराहना की गई है। आईएमएफ के द्वारा पिछले दिनों प्रकाशित रिसर्च पेपर में कोविड-19 की वजह से लगातार गए लॉकडाउन के प्रभावों की गरीबों पर मार को कम करने में अहम भूमिका निभाई है और इससे अत्यधिक गरीबी में भी कमी आई है। आईएमएफ के कायंपत्र में कहा गया है कि खाद्य सिब्सीडी कार्यक्रम कोविड-19 से प्रभावित वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर

अन्य वर्षों में गरीबी घटाने में सफल रहा है। दुनिया के अर्थविशेषज्ञ यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोविड-19 के बीच भारत में खाद्यान्न के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचे सुरक्षित खाद्यान्न भंडारों के कारण ही देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध होने के कारण वे गरीबी के दलदल में फंसने से बच गए। देश में लगातार बढ़ता हुआ रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूती प्रदान कर रहा है। चालू कृषि वर्ष 2022-23 में 3305.34 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। लेकिन वर्ष 2023-24 में गेहूं और दलहन उत्पादन में कमी के संकेत सामने आ रहे हैं। ऐसे में देश में खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक खाद्यान्न की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत 142.86 करोड़ लोगों की आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। चूंकि खाद्यान्न के केंद्रीय प्लान में सालाना 780 से 800 लाख टन गेहूं और चावल की खरीद होती है। पीडीएस के तहत अनाज देने के लिए 500 से 590 लाख टन अनाज की जरूरत होती है। वर्ष 2023-24 में केंद्र ने एनएफएसए में 600 लाख टन गेहूं और चावल का आवंटन किया है। ऐसे में जब देश में अधिक खाद्यान्न उत्पादन की जरूरत है, तब खाद्यान्न को बर्बादी से बचाने के लिए खाद्यान्न भंडारण की अधिक क्षमता भी जरूरी है। इस परिप्रेक्ष्य में हाल ही में 31 मई को सरकार के द्वारा स्वीकृत

खाद्यान्न भंडारण क्षमता योजना महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। यह योजना लगभग एक लाख करोड़ रुपए के खर्च के साथ शुरू होगी। इस समय देश का खाद्यान्न उत्पादन लगभग 3100 लाख टन है, जबकि भंडारण क्षमता कुल उत्पादन का केवल 47 प्रतिशत ही है। यद्यपि भारत दुनिया का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक देश है, लेकिन खाद्यान्न भंडारण में बहुत पीछे है। अनाज के अन्य बड़े उत्पादक देशों चीन, अमेरिका, ब्राजील, यूक्रेन, रूस और अफेन्टीना के पास खाद्यान्न भंडारण क्षमता वार्षिक उत्पादन की मात्रा से कहीं अधिक है। ऐसे में देश में खाद्यान्न भंडारण की जो क्षमता फिलहाल 1450 लाख टन की है, उसे अगले 5 साल में सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करके कुल खाद्यान्न भंडारण क्षमता 2150 लाख टन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह बात महत्वपूर्ण है कि देश में एक ओर गरीबों के कल्याण के लिए लागू की गई विभिन्न सरकारी योजनाएं मसलन सामुदायिक रसोई, वन नेशन वन राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत पोषण अभियान, समग्र शिक्षा जैसी योजनाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी के स्तर में कमी और स्वास्थ्य व भुखमरी की चुनौती को कम करने में सहायक रही हैं। उनके कार्यान्वयन की दिशा में अभी बहुत अधिक कारगर प्रयासों की जरूरत बनी हुई है। चूंकि कोविड-19 के कारण देश में डिजिटल शिक्षा की जरूरत बढ़ गई है और इसकी अहमियत रोजगार में भी बढ़ गई है। ऐसे में गरीब एवं कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के मौके जुटाने के लिए एक ओर सरकार के द्वारा डिजिटल शिक्षा के रास्ते में दिखाई दे रही कमियों को दूर करना होगा, वहीं दूसरी ओर कौशल शिक्षा के साथ नए स्किल्स सीखने होंगे। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना होगा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने के लिए रोजगार की गुणवत्ता बढ़ाने और उनके लिए रोजगार के अधिक अवसरों के लिए भी अधिक प्रयास करने होंगे। ऐसा होने पर ही गरीबी घटाने और आय में असमानता को कम करने में सफलता प्राप्त की जा सकेगी। फिलहाल गरीब और अमीर की आय में दिन-रात का अंतर है।

संपादक की कलम से

राज्यपाल ‘वीटो’ नहीं हैं

बीते कल 26 नवम्बर था। 1949 में इसी तारीख को संविधान सभा ने ‘स्वतंत्र भारत के संविधान’ को अंतिम स्वीकृति दी थी। यहीं से भारत के संसदीय लोकतंत्र की यात्रा आरंभ होती है। इस दिन को देश ‘संविधान दिवस’ के तौर पर मनाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अच्छे-अच्छे बयान देते हैं। समारोह भी मनाए जाते हैं। संविधान को 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया, लिहाजा उस दिन देश ‘गणतंत्र दिवस’ मनाता है। संविधान और लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका और राज्यपाल भी हैं। इन दिनों सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों को कुछ राज्यपालों के खिलाफ तल्ख और नाराज टिप्पणियां करनी पड़ी हैं। शीर्ष अदालत को पंजाब के राज्यपाल को आधार बनाकर राज्यपाल की विवेकाधीन, संवैधानिक और मनमानी शक्तियों की एक निश्चित सीमा तय करनी पड़ी है, ताकि तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना के राज्यपाल भी सबक सीख सकें। यदि राज्यपाल संविधान के मुताबिक अपना दायित्व पूरा नहीं करेंगे, तो सर्वोच्च अदालत की संविधान पीठ को अधिक कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। संविधान में सभी पदों की शक्तियों और दायित्वों को अच्छी तरह परिभाषित किया गया है। तो फिर क्या कारण हैं कि शीर्ष अदालत को राज्यपालों के खिलाफ कठोर टिप्पणियां करनी पड़ी हैं। बल्कि उनके व्यवहार को ‘असंवैधानिक’ और ‘सियासी’ करार देना पड़ा है? एक कारण अनुच्छेद 200 हो सकता है, जिसमें अधूरी व्याख्या की गई है कि राज्यपाल कितने समय में बिलों को अपनी स्वीकृति देंगे। इस परिप्रेक्ष्य में देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को यहां तक कहना पड़ा कि लोकतंत्र और संविधान में राज्यपाल सर्वेसर्वा नहीं हैं। वे निर्वाचित जन-प्रतिनिधि भी नहीं हैं।

राष्ट्रपति ने, केंद्रीय कैबिनेट की सफािशरि पर, उन्हें नियुक्त किया है। वे लोकतंत्र में निर्वाचित विधानसभा पर ‘वीटो’ नहीं कर सकते। संविधान और लोकतंत्र की मूल ताकत जनता द्वारा चुने गए विधायकों में ही निहित है। राज्यपाल विधानसभा सत्र को ‘अवैध’ करार नहीं दे सकते। जस्टिस चंद्रचूड़ ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन पर परवाल किया है कि वह तीन साल से क्या कर रहे थे? पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को लेकर टिप्पणी की गई है कि क्या उन्हें अंदेशा है कि वह आग से खेल रहे हैं? इस तरह संसदीय लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। राज्यपाल राज्यों के ‘सांकेतिक प्रमुख’ होते हैं। असली शक्तियां विधायिका के पास होती हैं। यह बीते 50 सालों के दौरान विभिन्न न्यायिक फैसलों में बार-बार दोहराया गया है। फिर भी राज्यपाल सालों तक उन विधेयकों पर कुंडली मारे बैठे रहते हैं, जिन्हें विधानसभा ने पारित किया है। इस तरह राज्यपाल मौजूदा राज्य सरकार की नीतियों और विधायिका के इरादों को लगातार दरकिनार करते रहे हैं। यह संविधान और लोकतंत्र की निहित भावना नहीं है। शुक्र है कि संविधान सभा ने ‘निर्वाचित राज्यपाल’ के प्रावधान तय नहीं किए। यह व्यवस्था की गई कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही नियुक्त किया जाएगा। इस संवैधानिक प्रावधान का भी लगातार उल्लंघन होता रहा है। अब ये तमाम विवादित राज्यापाल भाजपा या संघ परिवार के सदस्य रहे हैं अथवा उनके समर्थित चेहरे हैं, लिहाजा गैर-भाजपा राज्य सरकारों के प्रति राज्यापालों का रवैया पूरी तरह सियासी है। लिहाजा संसद में संविधान संशोधन लाया जाए और राज्यपाल की भूमिका को नए ढंग से परिभाषित किया जाए, या अदालत को ही कोई फैसला सुनाना चाहिए।

राय

पर्यटन की गुल्लक हैं मंदिर

हिमाचल में फिजुलखर्चियां रोक कर आर्थिक संसाधनों से बड़ी तस्वीर खींची जाए, तो विकास की तारीर और भविष्य को उम्मीद बदल जाएगी। फिजुलखर्ची बजटीय भाषणों से निकल कर सियासी खुशफहमियों के दौर में, जो मकसद चुनती रही वे सारे मुहारेबे बेकार हो चुके हैं। प्रशासनिक ढंरे, विभागीय विस्तार, टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन, अनावश्यक दफ्तरों का कंकाल और सरकारी संसाधनों से सत्ता के पोषण में जाया हुए धन की समीक्षा हो सकती है, लेकिन वुद्धि और समुद्धि के क्षेत्रों को नजर अंदाज कर देने से भी ठहराव आया है। नीतियों के चुंबक हमेशा कर्मचारी वर्ग के सरकारी प्रश्रय को आकर्षित करते रहे जबकि प्रोथ्य सेक्टर में अग्रसर निजी प्रयासों को पथ नहीं मिला। उदाहरण के लिए परिवहन और पर्यटन क्षेत्रों में निजी भूमिका से सार्वजनिक क्षेत्र लड़ता रहा है और आज भी यह प्रयास या खुशफहमी है कि प्रदेश जलवा दिखाएगा। प्रदेश में निजी स्तर पर वोल्वो या डीलक्स बसों के मार्फत आते टूरिज्म को पहचाने तो मालूम हो जाएगा कि हिमाचल की आर्थिक क्षमता को बढ़ाया कैसे जा सकता। इसी तरह पर्यटन की व्याख्या या समीक्षा के लिए निजी भूमिका को अंगीकार करें, तो नित नई संभावनाएं परिलक्षित होंगी। हम हिमाचल के पर्यटन को चोटी पर देखना चाहते हैं, लेकिन इसके आधार पर धार्मिक पर्यटन के विस्तार को भूल जाते हैं। मंदिरों की आय को खर्च करने की अदा ने यह नहीं सोचा कि इसके सदुपयोग से हिमाचल भी दक्षिण भारत के मंदिरों की तर्ज पर पांच से दस हजार करोड़ की आर्थिकी विकसित कर सकता है। विटंबना यह है कि अभी अब सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके मंदिरों की आय पर नजर रखने वाले पैदा होने लगे हैं।

इसी बीच सरकार ने चार दशक पुरानी नियमावली को बदल कर मंदिरों के खजाने में फंसे सोने व चांदी के भंडार व पैसे की गुल्लक का इस्तेमाल करने का रास्ता साफ किया है, लेकिन इसकी मर्यादा व लक्ष्मण को हमेशा याद रखना होगा। हिमाचल के तकरीबन तीन दर्जन मंदिरों के पास 600 किलोग्राम सोना व 235 किंवदंत चांदी के अलावा समाज तीन सौ करोड़ के लगभग धनराशि उपलब्ध है। यह सारा धन अगर धार्मिक पर्यटन के विकास में इस्तेमाल हो तो आर्थिकी का नक्शा बदल सकता है, लेकिन इससे पहले तमाम मंदिरों को एक केंद्रीय ट्रस्ट या मंदिर विकास प्रतिकरण के दायरे में लाना होगा, ताकि वार्षिक योजना के तहत मंदिर विकास परियोजना के खाके में बजट बनाया जा सके। मंदिर आय से रेलवे विकास परियोजना को अगर अंब-अंदौरा से प्रथम चरण में ज्वालामुखी तक बढ़ाया जाए, तो इसी की आय से अगर हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी व कांगड़ा के तमाम धार्मिक स्थल एक सर्किट के रूप में जुड़ जाएंगे और इससे रेलवे का सामाजिक व आर्थिक हस्तक्षेप भी कारगर सिद्ध होगा। मंदिर आय से धार्मिक पर्यटन का औद्योगिक महत्व आगे बढ़ाया जा सकता है। धार्मिक पर्यटन उद्योग के रास्ते हिमाचल के धूप, पारंपरिक पेड़ों, रोट तथा उपहार वस्तुओं के उत्पादन को अलग से बढ़त दी जा सकती है। मंदिर आय से हिमाचल में सांस्कृतिक पर्यटन को देव स्थलों पर निखारा जा सकता है। दार्णक को अर्थ है आईना, शीशा, प्रतिबिंबित करने वाली कोई वस्तु, लेकिन साहित्य का यह एक पहलू है और यह साहित्य की आधी परिभाषा है। साहित्य का दूसरा पहलू है- समाज निर्माण की परिकल्पना सुन। कैसा समाज हो, कैसा संसार हो, कैसा सामाजिक परिवेश हो, इसकी परिकल्पना भी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। ‘लेखनी’ खंड काव्य की कुछ पंक्तियों में है- अनुसार- ‘दर्शन-सत्य को कभी बिम्ब

अपना देश व्यस्तता के मामले में दुनिया को पछाड़ सकता है, आश्चर्य यह कि इसकी कोई प्रतियोगिता नहीं होती। हमारी व्यस्तता थोड़ी-सी भिन्न है, लिहाजा इसे न तो पहचाना जा सकता और न ही कंकड़ा जा सकता। लोगबाग अति व्यस्त मिल जाएं, तो भी मालूम नहीं होता कि वे व्यस्त हैं किस्लिए। कुछ लोगों को नजर आता है कि भारत में व्यस्तता के दो बड़े कारण हैं। या तो मनोरंजन में व्यस्त हैं या किसी त्रासदी से भी व्यस्त हो सकते हैं। हमारा मनोरंजन कोई जमीनी नहीं। कोई जोर से नारा लगा दे कि अतीत में हिंदोस्तान जहां पहुंच गया था, वहां आज भी कोई नहीं पहुंच सकता, तो भी हमारा मनोरंजन हो जाता है। अब क्रिकेट को ही लो, हमारा मनोरंजन खेल नहीं दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में अपना नाम और जोश ढूंढना है।

विचार

एक उपन्यास ने विज्ञान और तर्क के कारण आई हुई शिथिलता को प्रश्नों के घेरे में लेकर कैसे बहुत बारीकी से आस्तिकता, सकारात्मक विचारों, सृजन और नैतिकता का एक बेहतर नमूना पेश किया, यह साहित्य का निर्माण वाला पहलू है जोकि बहुत समय से अनुपस्थित दिख रहा है। साहित्य में कल्पना और कलात्मकता तो दिखती है, लेकिन समाज निर्माण की परिकल्पना देखने को नहीं मिलती जिसकी आज बहुत आवश्यकता है”

साहित्य सामाजिक और व्यक्तिगत स्थिति और समस्या की जहां एक ओर अभिव्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर यह उसकी अग्रिम परिकल्पना भी है। हम अक्सर एक वाक्य कहते हैं कि ‘साहित्य समाज का दर्पण है’, इसका सीधा अभिप्राय है कि साहित्य आपकी व्यक्तित्व या सामाजिक स्थिति और समस्या को अभिव्यक्त करता है। आपके साथ क्या घटित हो रहा है, यह आपकी भावना, संवेदना और विचारों को एक खुला मंच प्रदान करता है। हम एक परिभाषा की तरह कहते हैं तो हम कहते हैं कि ‘साहित्य समाज का दर्पण है’। दर्पण का अर्थ है आईना, शीशा, प्रतिबिंबित करने वाली कोई वस्तु, लेकिन साहित्य का यह एक पहलू है और यह साहित्य की आधी परिभाषा है। साहित्य का दूसरा पहलू है- समाज निर्माण की परिकल्पना सुन। कैसा समाज हो, कैसा संसार हो, कैसा सामाजिक परिवेश हो, इसकी परिकल्पना भी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। ‘लेखनी’ खंड काव्य की कुछ पंक्तियों में है- अनुसार- ‘दर्शन-सत्य को कभी बिम्ब

भले ही वल्ड कप आस्ट्रेलिया ले जाए, लेकिन हमारे मनोरंजन की व्यस्तता देखिए कि देश के प्रधानमंत्री को हमने क्रिकेट स्टेडियम में लगातर कई घंटे काम करते देख लिया। दूसरी ओर उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 41 लोग जीने के लिए व्यस्त रहे। यह फैसला सरकार को करना होता है कि वह कहां स्वयं को व्यस्त और कहां देश को व्यस्त दिखाए।

दरअसल सरकार अपने अपनी व्यस्त प्रणाली से आम जनता का मनोरंजन कर रही हैं। कई बार और बार-बार यह भी देखा गया कि किसी अस्पताल की व्यस्तता में मरीजों का मनोरंजन हो जाता है। अस्पताल की व्यस्तता में एक ही बेड पर दो-दो मरीज सुला देना मनोरंजन की प्रक्रिया ही

शव संवाद-19

नहीं, कई बार मानवता की संज्ञा में बदल जाता है। मरीज के तीमारदार अपने के बजाय दूसरे मरीज को दवाई या खुराक खिला दें, तो यह मानवीय मनोरंजन है, जिसे विकसित देश नहीं जान सकते। हमारी व्यस्तता भीड़ में है, इसलिए आबादी पर नियंत्रण करने के बजाय हम मनोरंजन पैदा करते हैं। वर्षों से देश के मनोरंजन से केवल बुद्धिजीवी अछूता है, इसलिए भटक रहा है। उसे खबरिया चैनलों की व्यस्तता में भी मनोरंजन नहीं मिलता और न ही अखबारों की भाषा में उसे मुस्कुराने की फुर्सत मिलती। उसके लिए क्रिकेट में हार-जीत और सुरंग में भी जीने-मरने के सवाल एक जैसे पैदा हो रहे हैं। उदास बुद्धिजीवी को आजादी के बाद

कोई नहीं हंसा सका, हालांकि वह भी अपने नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्रियों तक के कारनामों में अपने आयेजन से ही उदास बुद्धिजीवी को मलाल यह था कि कहीं भारतीय टीम उसी के कारण ही तो नहीं हारी। वह पहली बार शर्मिंदा इसलिए भी था क्योंकि उसकी मौजूदगी के बावजूद मनोरंजन नहीं हो सका। इसी उधेड़बुन में बुद्धिजीवी आगे बढ़ रहा था कि उसने देखा कि लोगों का हुजूम व्यस्तता के बावजूद अपना मनोरंजन खुद ही कर रहा था। वहां कई राज्यों की चुनावी ट्राॅफियां आपस में लड़ रही थी। वहां मनोरंजन की धड़ें बंदी स्पष्ट थी। भीड़ में जो सियासत पैदा कर रहे थे, उनके लिए ट्राॅफी का

उछलना मनोरंजन था, तो जो तमाशाबीन थे, वे चुनावी ट्राॅफियों के टूटने का इंतजार कर रहे थे। बुद्धिजीवी हर ट्राॅफी में भारतीय लोकतंत्र की गर्दन देखते हुए सोच रहा था, ‘कितना निर्दयी है लोकतंत्र के माध्यम से जनता का मनोरंजन करना। आखिर जीत-हार के बीनें की टूटेंगी तो चुनावी ट्राॅफी ही।’

उसे लगा कि भारतीय मनोरंजन के लिए कितने चुनावी पापड़ बेलने पड़ते हैं। तभी उसने देखा कि भीड़ की व्यस्तता में दब गई एक ट्राॅफी कराह रही थी। किसी तरह उसको उठाकर वह आगे बढ़ गया। अब सवाल इसे महफूज रखने का था। उसे लगा कि जनता के हर कोने में सियासत इसके निशान मिटा देगी, इसलिए बचाने के लिए कोई कन्न ढूंढी जाए या शमशानघाट। उसने शमशानघाट में खुले मुंह की ट्राॅफी को सजा दिया।

साहित्य और समाज का समन्वय



रामराज्य! इस विश्व के पहले कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण नामक एक महाकाव्य जहां एक ओर समाज की स्थिति और समस्याओं का वर्णन करता है वहीं आदर्श चरित्र राम तथा अन्य आदर्श चरित्रों के माध्यम से यह महाकाव्य रामराज्य की परिकल्पना की नींव रखता है। अंग्रेजी में रामराज्य को ‘यूटोपिया’ शब्द से सम्बन्धित देखा गया है। राम एक आदर्श पिता, पति, पुत्र, भाई, राजा और राजनीतिज्ञ हैं और उनके साथ अन्य आदर्श चरित्र भी बहुत सी आदर्श क्रियाओं द्वारा उच्च मानवीय गुणों का प्रतिपादन करते हैं।

रामायण के दो मुख्य भाग हैं, पहले भाग में सामाजिक ढांचे को यह महाकाव्य प्रतिबिंबित करता है, तो दूसरे भाग में रामराज्य का एक नमूना पेश करता है जिसमें एक सम्पन्न, सुव्यस्त, प्रसन्न, स्वस्थ, सृजनशील और शांतिप्रिय समाज है। हमने देखा है कि रामायण के पहले भाग में बहुत

सी पारिवारिक, व्यावहारिक, सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल रहती है जिसमें स्वयं मुख्य चरित्र राम भी इसका शिकार होते हैं, तो दूसरे भाग में राजा बने राम द्वारा किए गए महत्वपूर्ण बदलावों, सही समाज-कल्याणकारी योजनाओं से रामराज्य की स्थापना होती है और यहीं लोग राजा राम को प्रभु श्रीराम संबोधित करते हैं। अतः साफ जाहिर होता है कि साहित्य के दो मुख्य पहलू हैं- एक तो ‘साहित्य समाज का दर्पण है’, दूसरा ‘साहित्य एक दर्शन भी है’, जो एक आदर्श या भव्य समाज की परिकल्पना करता है और परियोजना हेतु सामाजिक ढांचे के नमूने पेश करता है। आज फिर से समाज के निर्माण में साहित्य के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू जिसमें साहित्य दूरदर्शिता रखते हुए दार्शनिकता के पुट के साथ समाज के ढांचे के नमूने पेश करे और समाज के निर्माण में सहायक हो, फ्रेडरिक नीत्से को अंग्रेजी में अनुवादित फ्रेंच उपन्यास ‘दस स्पॉक जाराथुस्रा’ इसका एक

महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक उपन्यास ने विज्ञान और तर्क के कारण आई हुई शिथिलता को प्रश्नों के घेरे में लेकर कैसे बहुत बारीकी से आस्तिकता, सकारात्मक विचारों, सृजन और नैतिकता का एक बेहतर नमूना पेश किया। यह साहित्य का निर्माण वाला पहलू है जोकि बहुत समय से अनुपस्थित दिख रहा है। साहित्य में कल्पना और कलात्मकता तो दिखती है, साहित्य बहुत सी विधाओं के माध्यम से समाज का दर्पण बनने में भी सफल है, लेकिन समाज निर्माण की परिकल्पना देखने को नहीं मिलती जिसकी आज भारत को बहुत आवश्यकता है, और लेखनी की कुछ पंक्तियां : ‘कैसा मानव, कैसा संसार हो/कैसा आवरण, कैसा विचार हो/सामाजिकता के पूर्ण वृत में/सृजनता का संचार हो/आचार, विचार, संसार रचूंगी/न चुप रही, न रहूंगी/मैं लिखूंगी, मैं कहूंगी।’

पंकज ‘दर्शी’

अत्याधुनिक उद्योगों के लिए जरूरी क्रिटिकल खनिज जुटाने में लगी सरकार, जानिए फ्यूचर प्लान

परिवहन विशेष न्यूज

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर सौर ऊर्जा व सेमीकंडक्टर जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों में आत्मनिर्भर बनने की नीति को आगे बढ़ाने शुरू कर दिया है। इसको लेकर मंगलवार को खनन मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित विदेशी राजदूतों व उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक बड़ी बैठक बुलाई है। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर सौर ऊर्जा व सेमीकंडक्टर जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों में आत्मनिर्भर बनने की नीति को आगे बढ़ाने शुरू कर दिया है। इस काम में सबसे जरूरी होगा क्रिटिकल माइंस यानी लिथियम, कोबाल्ट, टाइटेनियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट जैसे दो दर्जन से ज्यादा खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। चूंकि इन खनिजों का अभी उत्खनन विदेशों में ही हो रहा है इसलिए विदेशी सरकारों की भूमिका अहम होगी।

मंगलवार को खनन मंत्रालय की बड़ी बैठक
इस क्रम में एक तरफ विदेशी सरकारों से प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और उद्योग व वाणिज्य मंत्रों के स्तर पर बातचीत की जा रही है तो दूसरी तरफ खनन मंत्रालय घरेलू क्रिटिकल मिनिरल नीति बनाने भी जा रही है। मंगलवार को खनन मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित विदेशी राजदूतों व उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक बड़ी बैठक बुलाई है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने रिनीवेबल इनर्जी, संचार क्षेत्र में मैनुफैक्चरिंग और बिजली से चलने वाले वाहनों के क्षेत्र में जो बड़ी महत्वाकांक्षी नीतियां बनाई हैं उसकी सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि हम इन उद्योगों के लिए जरूरी क्रिटिकल खनिजों की आपूर्ति कितना सुनिश्चित कर पाते हैं।

भारत का फ्यूचर प्लान
एपल ने भारत में मोबाइल फोन की मैनुफैक्चरिंग शुरू कर दी है, लेकिन इसके बहुत सारे उपकरण अभी भी चीन से तैयार हो कर आते हैं। यह भारत में तभी पूरी तरह से बनना शुरू होगा जब यहां घरेलू स्तर पर जरूरी क्रिटिकल माइंस मिलने लगे। इसी तरह से भारत में वर्ष 2030 तक 4.50 लाख मेगावाट क्षमता की रिनीवेबल ऊर्जा क्षमता लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सोलर पैनल देश में ही बनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन यह काम तभी होगा जब आर्सेनिक, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम, कैडमियम, सिलिकन जैसे क्रिटिकल माइंस की व्यवस्था हो। इसी



तरह की जरूरत इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में भी जरूरत होगी और सेमीकंडक्टर निर्माण में भी।

क्या है नियम ?
17 अगस्त, 2023 को खान व खनिज अधिनियम (एमएमडीआर) कानून में संशोधन करने से 24 तरह के क्रिटिकल माइंस के खनन के लिए निविदा जारी करने व ठेका देने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल गया है। सरकार कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन भी दे रही है। खनन मंत्रालय एक राष्ट्रीय क्रिटिकल माइंस नीति बनाने में जुटी है जिससे इस क्षेत्र में घरेलू आपूर्ति व आयात से आपूर्ति करने की स्थिति और स्पष्ट होगी। लेकिन यह सवाल भी सामने है कि भारत में इस तरह के खनिजों की उपलब्धता कितनी है।

संबंधित विभागों के साथ मंत्रालय का संपर्क

खनन मंत्रालय दूसरे देशों के संबंधित विभागों व मंत्रालयों के साथ भी लगातार संपर्क में है। आस्ट्रेलिया में इस तरह के कई खनिजों के अकूत भंडार हैं। भारत व आस्ट्रेलिया में इसके लिए समझौता भी हुआ है। आस्ट्रेलिया के भारत में राजदूत फिलिप ग्रीन ने पिछले दिनों दैनिक जागरण को बताया कि- दोनों देशों की सरकारों ने लिथियम से जुड़ी दो और कोबाल्ट से जुड़ी परियोजनाओं का चयन किया है जहां हम साथ काम करेंगे। हम भारत को इनके खनन में साझेदार बनाना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में काफी जरूरी हैं। क्रिटिकल माइंस खनन का आस्ट्रेलिया के पास 60 सालों का अनुभव है।

उन्होंने आगे कहा कि मैं भारतीय उद्योगों से कहूंगा कि इन खनिजों की काफी ज्यादा मांग है और अमेरिका,

यूरोप, उत्तरी एशिया सब इनकी मांग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भारतीय कंपनियों को ये खनिज मिले, लेकिन उन्हें तेजी से फैसले करने होंगे।

क्रिटिकल माइंस क्या हैं ?
अगस्त, 2023 में खनिज मंत्रालय की तरफ से गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 30 खनिजों को क्रिटिकल माइंस घोषित किया है। इन्हें रणनीतिक खनिज भी कहा जाता है। ये हैं एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हाफनियम, इंडिमियम, लिथियम, मोलीब्डेनम, नायोबियम, निकल, पीजीइ, फॉस्फोरस, आरइइ, रेनियम सिलिकन, स्टोर्नटियम, टैटालम, टेलुरियम, टिन, टाइटेनियम, वानाडियम, जिर्कोनियम, सेलैनियम और कैडमियम।

एलआईसी एजेंटों को सीखा रही डिजिटल टेक्नोलॉजी ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक बढ़ सकता है कंपनी का व्यवसाय

देश में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के चेयरमैन ने दैनिक जागरण से बात करते हुए कहा कि भविष्य में कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा विस्तार का लक्ष्य लेकर चल रही है। अभी एलआईसी का कुल व्यवसाय का 20 से 22 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय बढ़ाने के लिए कंपनी वहां अधिक से अधिक एजेंट नियुक्त कर रही है।

मुंबई। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ग्रामीण क्षेत्रों में अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए कर्मक कस रही है। कंपनी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती का कहना है कि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में एलआईसी का व्यवसाय 40-50 प्रतिशत तक जा सकता है।

देश में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के चेयरमैन ने दैनिक जागरण से बात करते हुए कहा कि भविष्य में कंपनी

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा विस्तार का लक्ष्य लेकर चल रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा एजेंट नियुक्त कर रही LIC

अभी एलआईसी का कुल व्यवसाय का 20 से 22 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय बढ़ाने के लिए कंपनी वहां अधिक से अधिक एजेंट नियुक्त कर रही है। मोहंती के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बीमा उत्पाद ऐसे होने चाहिए, जिनमें ग्राहक आसानी से प्रीमियम भर सकें। ग्रामीण ग्राहक बीमा सुरक्षा के साथ-साथ अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं।

इन बातों को ध्यान में रखकर ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इनका उत्पाद शहरी क्षेत्रों के ग्राहक भी कर रहे हैं। एलआईसी अपने पालिसी वितरण में विविधता लाने की रणनीति भी तैयार कर रही है। अभी 96 प्रतिशत पालिसी एजेंटों के जरिये बेची जाती है, लेकिन अब डिजिटल ट्रांसफार्मेशन के साथ-साथ दूसरे माध्यमों के इस्तेमाल की



रणनीति भी तैयार की जा रही है। **एजेंटों को सीखा रही डिजिटल टेक्नोलॉजी**
एलआईसी अपने एजेंटों को डिजिटल तकनीक से सुसज्जित कर रही है, बैंकएश्योरेंस जैसे अन्य विस्तृत माध्यमों का भी उपयोग करने जा रही है। एलआईसी के 'आनंद एप' से पिछले वर्ष 8,11,000 पालिसी बिकी थीं। इस वर्ष

बढ़ेगी और पालिसी की निरंतरता टूटने का सिलसिला भी कम होगा।

अगले महीने आएंगी नॉन-पार्टिसिपेटिंग पालिसी

जीवन बीमा के क्षेत्र में बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र की कंपनियां एवं डाक विभाग जैसे सरकारी विभाग भी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हालांकि एलआईसी चेयरमैन का मानना है कि भारत में बीमा क्षेत्र का बाजार बहुत बड़ा है। इसमें सभी के लिए विस्तार की पर्याप्त गुंजाइश है। इसके साथ ही एलआईसी की साख पर भरोसा जताते हुए वह कहते हैं कि कड़ी प्रतियोगिता के बीच भी कंपनी हर वर्ग के ग्राहकों में अपनी पैठ बढ़ाती जा रही है।

उनके अनुसार दिसंबर के प्रथम सप्ताह में एलआईसी नियमित प्रीमियम वाली एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग पालिसी लेकर आएंगी। बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई इस पालिसी में ग्राहकों को जीवन पर्यंत रिटर्न दिया जाएगा।

रेमंड चीफ गौतम सिंघानिया ने कर्मचारियों और बोर्ड मैबर्स बताया, सुचारु रूप से चल रहा कंपनी का कामकाज

परिवहन विशेष न्यूज

रेमंड प्रमुख गौतम सिंघानिया ने कंपनी के कर्मचारियों और बोर्ड मैबर्स को मेल कर कंपनी के कामकाज को लेकर जानकारी दी है। पिछले हफ्ते पत्नी नवाज से अलग होने के बाद उन्हें लेकर मीडिया में तमात तरह की खबरें चल रही थी जिसके बाद उन्होंने कंपनी से जुड़े लोगों को आश्वस्त करने के लिए मेल लिख कंपनी में कामकाज पहले की तरह सुचारु रूप से चलने की बात कही है।

नई दिल्ली। रेमंड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) गौतम सिंघानिया ने कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों को आश्वस्त किया है कि कंपनी का कामकाज पहले की तरह चल रहा है और इसके सुचारु संचालन के लिए वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

इस महीने की शुरुआत में पत्नी नवाज से अलग होने का एलान करने वाले गौतम सिंघानिया ने कहा एक कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों को भेजे एक आंतरिक मेल में कंपनी में सबकुछ ठीक-ठाक से चलने की बात कही है।

मेरे निजी जीवन को लेकर मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, उस पर मैंने किसी तरह की टिप्पणी नहीं करने का फैसला किया है। अपने परिवार की गरिमा बनाए रखना मेरे लिए सर्वोपरि है। जहां तक कंपनी के सीएमडी के तौर पर मेरी जिम्मेदारी की बात है तो वह मैं पहले की तरह निभा रहा हूं। मैं आपको आश्वसन देता हूं कि रेमंड में सबकुछ पहले की तरह ही चल रहा है।

पिछली तिमाही में किया अच्छा प्रदर्शन

गौतम सिंघानिया ने कंपनी के कर्मचारियों को भेजे गए अपने मेल में आगे कहा, आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों के दौरान हमने अपने व्यवसाय को तेजी से बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और पिछली नौ तिमाहियों में व्यवसाय में लगातार बढ़ोतरी के साथ पिछली तिमाही हमारे लिए सबसे



अच्छी रही है। **कर्मचारियों और बोर्ड सदस्यों को किया आश्वस्त**
जागरण ने जब रेमंड के प्रवक्ता से संपर्क कर इस आंतरिक मेल की पुष्टि की है। रेमंड के प्रवक्ता ने बताया कि गौतम

टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में लगाया है पैसा और शेयर अलॉटमेंट का है इंतजार, तो यहां जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Tata Technologies IPO को निवेशकों का जबरदस्त रिसॉन्स मिला है। इस आईपीओ को 69.43 गुना सब्सक्राइब किया गया है। आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशक अब शेयर अलॉटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने भी टाटा ग्रुप के आईपीओ में पैसा लगाया है तो हम आपको अलॉटमेंट चेक करने के आसान तरीके के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

नई दिल्ली। Tata Technologies की मार्केट में एंट्री हो चुकी है। पिछले हफ्ते खुले इस टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर अलॉटमेंट बीएसई और एनएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज में 30 नवंबर को होना है। टाटा ग्रुप की कंपनी ने आईपीओ के जरिए 3,042 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। 22 से 24 नवंबर को खुले इस आईपीओ का प्राइस बैंड रेंज 475 रुपये से 500 रुपये प्रति शेयर रखा गया था। टाटा ग्रुप का यह आईपीओ 19 साल बाद आया जिसे निवेशकों का भरपूर सहयोग मिला। इस आईपीओ को 69.43 गुना सब्सक्राइब किया है। IPO को सब्सक्राइब करने वाले निवेशक अब शेयर अलॉटमेंट का इंतजार रहे हैं। यहां हम आपको अलॉटमेंट चेक करने के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं।

Tata Tech IPO: कैसे चेक करें अलॉटमेंट
स्टेप 1 - सबसे पहले आपको BSE की वेबसाइट ओपन करनी है।

कम हुई मांग तो लुढ़क गए सोने और चांदी के दाम, जानिए आपके शहर में आज क्या है 24 कैरेट गोल्ड का रेट



देश में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। पिछले दिनों देश में धनतेरस और दिवाली को लेकर गोल्ड की डिमांड बढ़ गई थी हालांकि उस वक्त भी कीमतों में अधिक उछाल देखने को नहीं मिला था। ऐसे अगर आप सोने में निवेश के लिहाज के हिसाब से देख रहे हैं तो उससे पहले अपने शहर में सोने की कीमतों के बारे में जान लीजिए।

नई दिल्ली। दिवाली के अगले दिन यानी सोमवार 13 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। देश में पिछले दिनों धनतेरस और दिवाली के चलते सोने की मांग बढ़ी थी जिसके कारण कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी को मिली थी।

आज क्या है सोने का भाव ?

आज वायदा कारोबार में सोने की कीमत 93 रुपये गिरकर 59,659 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 93 रुपये या 0.16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59,659 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 10,649 लॉट का कारोबार हुआ। विशेषज्ञों की मानें तो सोने की कीमतों में गिरावट का कारण का श्रेय प्रतिभागियों द्वारा अपने पदों में कटौती है। वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में सोना 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,940.90 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। **क्या है आज चांदी की कीमत ?**

आज वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 727 रुपये गिरकर 69,305 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 727 रुपये या 1.04 प्रतिशत की गिरावट के साथ 69,305 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया, जिसमें 25,337 लॉट का कारोबार हुआ।

वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में चांदी 0.92 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22.08 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

क्या है सोने की स्पॉट कीमत ?

गुड रिटर्न के मुताबिक खबर लिखे जाने तक सोने की स्पॉट कीमत विभिन्न शहरों में इस प्रकार है: दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 60,640 रुपये है। नोएडा में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 60,640 रुपये है। मुंबई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 60,490 रुपये है। चैन्नई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 60,980 रुपये है। कोलकाता में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 60,490 रुपये है। बेंगलुरु में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 60,490 रुपये है। केरल में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 60,540 रुपये है। पटना में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 60,540 रुपये है। सूरत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 60,540 रुपये है। चंडीगढ़ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 60,640 रुपये है। लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 60,640 रुपये है।

देर रात तेज रफ्तार कार ने छह मजदूरों को रौंदा, एक की मौत

हादसे में मूलरूप से सीतापुर के लहरपुर गांव निवासी इस्लाम (22) की मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गए। घायलों में इस्लामुद्दीन, तौसिफ और इमामुद्दीन की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सेक्टर-83 में शनिवार आधी रात को तेज रफ्तार कार ने कंपनी से पैदल लौट रहे छह कर्मचारियों को टक्कर मार दी। हादसे में मूलरूप से सीतापुर के लहरपुर गांव निवासी इस्लाम (22) की मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गए। घायलों में इस्लामुद्दीन, तौसिफ और इमामुद्दीन की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वहीं मामूली रूप से घायल शईक और तालिब को प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोतवाली फेज टू पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार की तलाश में जुट गई है। कोतवाली फेज-2 स्थित प्लास्टिक का सामान बनाने वाली कंपनी में काम करने वाले छह कर्मचारी शिफ्ट खत्म होने के बाद शनिवार रात करीब 1:15 बजे घर जा रहे थे। सेक्टर-83 में एम्पल कंपनी के सामने सफेद रंग की तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में इलाज के दौरान इस्लाम ने दम तोड़ दिया।



वहीं पांचों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल तीन को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया है। नोएडा सेंट्रल जेन के एडीसीपी हृदयेश कठेरिया के मुताबिक घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही कार और चालक की पहचान कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचित कर दिया गया है।

ऑडी की टक्कर से युवक की मौत

एक अन्य घटना में सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र के खोदना गांव में बरात में आए युवक इरफान की ऑडी कार की टक्कर से मौत हो गई। घटना 23 नवंबर की है। इरफान के भाई फुरकान की शिकायत पर पुलिस ने ऑडी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जारचा पुलिस को दी शिकायत में गांव पटाडी निवासी फुरकान ने कहा है कि बड़ा भाई इरफान दोस्त की शादी समारोह में शामिल होने के लिए सूरजपुर आया था। खोदना गांव में ऑडी कार ने इरफान को

टक्कर मार दी।

हादसे में बुरी तरह घायल इरफान को अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद इरफान के ऑडी कार पर खड़े होकर डांस करने और चालक के अचानक कार चलाने से गिरकर मौत होने की सूचना वायरल हुई थी। हालांकि परिजनों ने इससे इन्कार किया है। परिजनों ने बताया कि इरफान को तीन संतानें हैं। इरफान की मौत के बाद उसके परिजन का रोककर बुरा हाल है।

क्या विपक्ष के सवाल की डर से बिधानसभा बंद कर दिया गया ?



मनोरंजन सासमल , ओडिशा

भुबनेश्वर: जो राज्य में पहले कभी नहीं हुआ. इसे वर्तमान विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में बिजेडी ने दिखाया था. क्योंकि निर्धारित समय से विधानसभा के लिए साइन-ए-डे की घोषणा करना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन विधानसभा को केवल 4 दिनों में बंद करना नई बात थी। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है।

महज 4 दिनों में ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को बंद करने की राजनीति ने तूल पकड़ लिया है. मोहन माझी विपक्षी पार्टी के मुख्य सचिव हैं. प्रश्न सीधे परिसर में पड़े गए. प्रत्येक विधायक के पास 8 प्रश्न हैं जबकि 147 विधायकों के पास कई प्रश्न हैं। सरकार ने जानबूझकर सदन को बंद कर दिया. क्या सरकार

के पास विधायकों के सवालों का जवाब देने का समय नहीं है ?

बीजेडी नेता और मुख्यमंत्री बी कहते हैं: "गरीब लोगों की ताकत बीजू जनता दल है." पल-पल टीम गांव पहुंचकर लोगों की बात समझ रही है। लेकिन गांधी मार्ग पर बैठे लोगों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है. विधानसभा में जो चर्चा हुई उससे सरकार का मुंह खुल गया होगा. इसलिए सरकार डर गई है और भाग गई है.

मोहन ने आरोप लगाया कि कैबिनेट में लाए गए आदिवासी भूमि हस्तांतरण संशोधन अधिनियम को लार्कर आदिवासी जमीन दलालों को समर्थन देने की साजिश की गई है. हालांकि, तय समय से पहले विधानसभा बंद होने से सरकार अब असमंजस की स्थिति में है.

सेल एग्रीमेंट-पावर ऑफ अटार्नी काफी नहीं:सु-कोर्ट



परिवहन विशेष। एसडी सेठी। प्रोपर्टी के टाइटल ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि किसी प्रोपर्टी के टाइटल ट्रांसफर के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज होना जरूरी है। कोर्ट के मुताबिक केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को टाइटल ट्रांसफर के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत संपत्ति का मालिकाना तथी हो सकता है जब रजिस्टर्ड दस्तावेज हो। कोर्ट ने जिस मामले में फैसला सुनाया है उसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि वह संपत्ति का मालिक है और संपत्ति उसके भाई द्वारा गिफ्ट डीड के तौर पर दी गई थी। उसका कहना है कि यह संपत्ति उसकी है और कब्जा भी उसका है। जबकि दूसरे पक्ष ने संपत्ति पर दावा करते हुए कहा कि उसके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी, हलफनामा और एग्रीमेंट- टू सेल है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना था कि जिन दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवादी ने दावा किया है वह मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अचल संपत्ति का मालिकाना हक बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के नहीं हो सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ने सहमति जताते हुए कहा कि बगैर रजिस्टर्ड दस्तावेज के अचल संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं हो सकता है। लिहाजा प्रतिवादी के दावे को खारिज किया जाता है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील भी स्वीकार कर ली। उल्लेखनीय है कि पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल वह दस्तावेज है जिसमें खरीदार और विक्रेता के बीच प्रोपर्टी से जुड़ी सारी डिटेल्स होती है। इसमें प्रोपर्टी की कीमत और फुल पैमेंट के बारे में सारी डिटेल्स होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी अधिकार है जो किसी प्रोपर्टी के मालिक द्वारा किसी दूसरे शख्स को दिया जाता है। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने से उक्त शख्स का उस प्रोपर्टी पर मालिकाना हक बिल्कुल नहीं होता है। पर वह सिर्फ खरीद या बिक्री से संबंधित फैसले कर सकता है।

कैलाश सोनी के नाम विश्व की सबसे बड़ी रोट्टी 185 किलो वजन (11.25x11.25) का रिकॉर्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा में 8 अक्टूबर को विश्व की सबसे बड़ी रोट्टी का विश्व कीर्तिमान बनाया गया था यह रिकॉर्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड (वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस) में दर्ज हो गया है इस रिकॉर्ड को महामंडलेश्वर स्वामी हंसाराम जी उदासीन के पावन हाथों से आज सर्टिफिकेट और मेडल राजस्थानी जन मंच अध्यक्ष भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी को हरी सेवा आश्रम मे प्रदान किया

राजस्थानी जन मंच अध्यक्ष कैलाश सोनी ने बताया की सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भीलवाड़ा शहर का नाम विश्व पटल पर छा जाने के लिए विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी रोट्टी का निर्माण 8 अक्टूबर को हरी सेवा धाम में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में किया गया इस रोट्टी का व्यास 11.25 फीट x 11.25 फीट और वजन 185 किलो की बनी थी इसको बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से 24 हलवाई की टीम द्वारा विश्व की सबसे बड़ी रोट्टी को 6 घंटे से अधिक समय में बनाया गया था इसको देखने के लिए भीलवाड़ा शहर सहित भीलवाड़ा जिला और आसपास के जिलों से आमजन इसी रोट्टी को बनते हुए देखने



के लिए आए थे इसका तवा लगभग 1000 किलो और साइज 16 गुना 12 फीट की थी इसको बनाने के लिए 1100 इंटो की भट्टी में 1000 किलो कोयले का इस्तेमाल किया गया था विदित रहेगी 2012 में गुजरात के जामनगर शहर में 10 फीट बाई 10 फीट की रोट्टी 145 किलो का वजन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी इस रिकॉर्ड को 8 अक्टूबर को तोड़ दिया गया था इस विश्व रिकार्ड के बनने के बाद भीलवाड़ा शहर का नाम विश्व पटल पर छा गया है इस दौरान लाडू लाल तेली नगर

परिषद उपसभापति रामनाथ योगी विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री गणेश प्रजापत हलवाई महावीर गुर्जर बाबा धाम के बाबूलाल टांक वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष मदन खटोड़ रेड क्रॉस सोसाइटी के रमेश कानावत भवानी शंकर दुदानी भारत विकास परिषद आजाद शाखा के अध्यक्ष अभिषेक सोमानी कुंज बिहारी जागेटिया अभिषेक लोहिया धीरज लोहिया सुशील छाजेड़ रमेश दरक सहित राजस्थानी जन-मंच विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद थे।

कटक की ऐतिहासिक बालीयात्रा आज से शुरू

मनोरंजन सासमल , ओडिशा, भुबनेश्वर : ऐतिहासिक कटक बाली यात्रा आज से शुरू होगई । आज बाली यात्रा के उद्घाटन के बाद यह 4 तारीख तक जारी रहेगी. कटक में साजिब कटक और फिश टनल बाली यात्रा के मुख्य आकर्षण हैं। यात्रा के दौरान 1200 से अधिक स्टॉल खोले जाएंगे। पाकिस्थल से यात्रियों के परिवहन के लिए विशेष ई-रिक्शा रखे गए हैं। थोड़ नियंत्रण के लिए 4 प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था की गई है। प्रतिदिन सुबह पथ उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए मैदान के भीतर 250 अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड गायिका अनु मलिक भाग लेंगी.



इस साल मेले में पहुंचे 10 लाख से ज्यादा लोग, आखिरी दिन पैर रखने की नहीं मिली जगह; मिली भारी छूट

सोमवार को गुरु पूर्णिमा की छुट्टी होने के कारण करीब एक लाख से ज्यादा लोगों ने मेला देखा। आखिरी दिन हॉल आठ से 12 में प्राइवेट कंपनियों के उत्पादों पर 60 फीसदी तक छूट मिली। शाम तक केवल एक स्टॉल पर दो-चार पैकेट ही बचे।

नई दिल्ली। दिल्ली में इस बार ट्रेड फेयर में 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। सोमवार को गुरु पूर्णिमा की छुट्टी होने के कारण करीब एक लाख से ज्यादा लोगों ने मेला देखा। आखिरी दिन हॉल आठ से 12 में प्राइवेट कंपनियों के उत्पादों पर 60 फीसदी तक छूट मिली। लोगों ने फुटवियर, घड़ियां, चश्मे, सुबह सैर करने के लिए कपड़े, सजावट के सामान, सूट, दुपट्टे, घर के लिए सजावट के सामान, एरोमा ऑइल, परफ्यूम इत्यादि की खरीदारी की। दोपहर को दो बजे से ही हॉल में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों के चलने के लिए जगह नहीं बची, फिर भी लोगों ने मेले का जमकर लुत्फ उठाया। खाने-पीने के सामानों की भी खूब बिक्री हुई। केरल के मसालों की खूब खरीदारी हुई।

आखिरी दिन दुकानदारों को मजबूरन ये कहना पड़ा कि मसाले खत्म हो गए। सबसे ज्यादा बिक्री काली मिर्च, लौंग, इलायची और नायिल तेल की हुई। शाम चार बजे तक पर्वेलियन में ये उत्पाद खत्म हो गए। यही हाल कश्मीरी कहवे का



रहा। जम्मू कश्मीर पर्वेलियन में करीब छह स्टॉल कहवा बेचने के लिए थे। शाम तक केवल एक स्टॉल पर दो-चार पैकेट ही बचे।

लोकल उत्पादों की जमकर बिक्री

मेले में लोकल उत्पादों की जमकर बिक्री हुई। यूपी पर्वेलियन में गाजियाबाद के दूध, दही, छाछ, घी, मिल्क शेक की जमकर बिक्री हुई। इसी तरह हॉल आठ में अनंद कपनी के दूध, मक्खन, लस्सी, जलेबी, दूध से निर्मित दूसरी मिठाइयों की जमकर बिक्री हुई। देर शाम तक इनके उत्पाद पर्वेलियन में बिक्री के लिए पहुंचते रहे।

छोटे बच्चों को ट्रॉली में लेकर घूमते रहे

मेला

मेले में बहुत से माता-पिता अपने छोटे बच्चों को पालने वाली ट्रॉली (प्रेम) में लेकर घूमते नजर आए। बुजुर्गों ने भी मेले में आकर समय बिताया और खरीदारी भी की। लोगों ने पसंदीदा राज्यों के फूड कोर्ट को ढूंढकर खाना खाया। फूड कोर्ट में भीड़ ज्यादा थी तो खाली जगहों पर, घास पर बैठकर कहीं भी खा लिया। थकने पर पर्वेलियन में ही कहीं किनारे बैठकर सुस्ता लिया और थोड़ी देर बाद फिर से मेला घूमने निकल पड़े। प्रगति मैदान के आसपास के बस स्टैंड पर जबरदस्त भीड़ रही। लोगों को बस पकड़ने के लिए इंतजार करना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर भी भारी भीड़ रही।

पिछले साल के मुकाबले दो लाख ज्यादा भीड़

आईटीपीओ के मेला विभाग के उप महाप्रबंधक कृष्ण कुमार ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब दो लाख ज्यादा लोग आए। पिछले साल करीब आठ लाख लोग ट्रेड फेयर पहुंचे थे। इस साल आगंतुकों का सटीक आंकड़ा एक-दो दिन में आएगा, लेकिन मोटे तौर पर ये माना जा सकता है कि करीब 10 लाख लोग 14 दिन में मेला देखने पहुंचे।

सिद्धू मूसेवाला के बाद निशाने पर था ये पंजाबी सिंगर, ऐसे बची थी जान; अर्श डल्ला गैंग के दो शूटर दबोचे

देश की राजधानी दिल्ली में रविवार देर रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप डल्ला के गिराव के पूर्णों के साथ पुलिस की मुठभेड़ रविवार और सोमवार की आधी रात को दिल्ली के मयूर विहार इलाके में हुई, पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों शूटर पंजाब के एक मामले में पैरोल खत्म होने के बाद से फरार थे, उन्होंने एक पंजाबी गायक पर हमला करने की योजना बनाई थी, स्पेशल सेल ने दोनों को दबोचा है, एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के बाद गैंगस्टर अर्शदीप सिंह डल्ला के दो शार्पशूटर राजप्रीत सिंह राजा और वीरेंद्र सिंह विष्मि को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के बाद दोनों को अक्षरधाम मंदिर रोड पर मयूर विहार के समाचार अपार्टमेंट के पास के गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान शार्पशूटरों की तरफ से पांच बार फायरिंग की गई। पुलिस ने बताया कि दो बुलेट पुलिस कर्मों को लगी हैं। जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने छह राउंड फायरिंग की। इसी मुठभेड़ में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जिसकी वजह से वह घायल हो गया। दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद एलबीएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। जहां दोनों चल रहा है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पास से दो बंदूक मिली है और 13 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा चोरी की बाइक भी बरामद की है। दिल्ली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि साल 2023 में इन दोनों शार्पशूटर को अर्शदीप डल्ला ने पंजाबी गायक एली मांगट की हत्या का काम सौंपा था। लेकिन इस मिशन ने दोनों कामयाब नहीं हो पाए थे। क्योंकि वह घर पर नहीं मिला था। यह मामला पंजाब के भटिंडा का है।

